twitter.com/divyadelhi facebook.com/divyadelhi infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DELHI/2013/54397

दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | गुरूवार, 17 अप्रैल, 2025 | वर्ष: 12, अंक: 161, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

वक्फ संशोधन कानून पर हुई' सुप्रीम' सुनवाई

इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा

नई दिल्ली

केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दो घंटे सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देशभर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। इस पर एसजी ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। यह अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक, कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं।' सुप्रीम कोर्ट अब गुरुवार 2 बजे सुनवाई करेगा। सुनवाई में अपीलकताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर्स में गैर-मुस्लिम और विवादों के निपटारों को लेकर मुख्य दलीलें दीं।

वक्फ बोर्ड बनाने की प्रक्रिया: अपीलकर्ता कपिल सिब्बल ने कहा,' हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं, जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं? इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूं?'

पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर: सिब्बल ने कहा, सरकार ने 8 अप्रैल से अधिनियम के लागू होने की अधिसूचना जारी की। तब से इसका लगातार विरोध हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 'वक्फ बाय यूजर' पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने 'वक्फ बाय यूजर' प्रावधान को हटाने पर केंद्र से जबाव मांगा। अदालत ने कहा कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बनी ज्यादातर मस्जिदों के पास बिक्री विलेख नहीं होंगे। इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा।

'वक्फ एक धार्मिक ट्रस्ट है'

नई दिल्ली

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के विरुद्ध जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी सहित विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन पर आधारित तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पक्षों की दलीलें दो घंटे तक ध्यान से सुनीं। जमीअत उलमा-ए-हिंद का प्रतिनिधित्व (याचिका संख्या 317/2025) में प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने किया, जबकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मंसूर अली खान हैं।

वक्फ डीड के कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता

सिब्बल ने कहा, 'केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे। अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। यह अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी मेंबर्स मुस्लिम होंगे। यहां 22 में से 10 मुस्लिम हैं। अब कानून लागू होने के बाद से बिना वक्फ डीड के कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक, कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसका फैसला अदालत को क्यों नहीं करने देते। संसद से 4 अप्रैल को पारित हुए वक्फ संशोधन बिल को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी।

14वीं-16वीं शताब्दी की मस्जिदों को कैसे रजिस्टर करेंगे: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाई यूजर के प्रावधान पर भी सवाल किया चीफ जस्टिस ने कहा कि कई पुरानी मस्जिदें हैं। 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी। उखक ने केंद्र से पूछा कि ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे। उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? ऐसे वक्फ को खारिज कर देने पर विवाद ज्यादा लंबा चलेगा। हम यह जानते हैं कि पुराने कानून का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ, लेकिन कुछ वास्तविक वक्फ संपत्तियां हैं। जिनके इस्तेमाल के दौरान लंबे समय से वक्फ संपत्ति के तौर पर पहचान हुई। वक्फ बाई यूजर मान्य किया गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी।

जस्टिस कुमार: हमें उदाहरण दीजिए। क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर-हिंदू हैं। सीजेआई हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक, कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसका फैसला अदालत को क्यों नहीं करने देते। एसजी वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। 1995 के कानून में भी ये जरूरी था। सिब्बल साहब कह रहे हैं कि मुतवल्ली को जेल जाना पड़ेगा। अगर वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वह जेल जाएगा। यह 1995 से है। सिब्बल-केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे। अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। यह अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी मेंबर्स मुस्लिम होंगे।

राष्ट्रपति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए छह जजों की नियुक्ति की

नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए छह जजों की नियुक्ति की है। राष्ट्रपति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जिन्हें जज के रूप में नियुक्त किया है उनमें जीतेन्द्र कुमार सिन्हा, अनिल कुमार दशम, संदीप जैन, अवनीश सक्सेना, मदन पाल सिंह और हरवीर सिंह शामिल हैं। आज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए दो जजों को नियुक्त करने की अनुशंसा की है। कॉलेजियम ने संजय परिहार और शहजाद अजीम को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए नियुक्त करने की सिफारिश की है।

एटीएम सुविधा युक्त ट्रेन बनी पंचवटी एक्सप्रेस

नई दिल्ली

भारतीय रेलवे ने मुंबई-मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में देश के पहले ऑनबोर्ड स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसकी शुरूआत से यात्रियों को सफर के दौरान चलती ट्रेन में नकदी निकासी का विकल्प मिल जाएगा। इसके साथ ही यह ट्रेन एटीएम सुविधा से युक्त देश की पहली ट्रेन बन गई है।

चार दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस 21 से 24 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। उनके साथ द्वितीय महिला उषा वेंस, उनके बच्चे और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्य भी होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह उपराष्ट्रपति वेंस की पहली भारत यात्रा होगी। यात्रा के दौरान, वे 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधिमंडल के दिल्ली में अन्य कार्यक्रम होंगे और 24 अप्रैल को वाशिंगटन डी.सी. के लिए प्रस्थान करने से पहले उनका जयपुर और आगरा जाने का भी कार्यक्रम है। मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान 13 फरवरी को जारी भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के परिणामों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

जस्टिस गवई होंगे अगले मुख्य न्यायाधीश

नई दिल्ली

भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के लिए न्यायमूर्ति भूषण आर गवई के नाम की सिफारिश की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिफारिश विधि मंत्रालय को भेज दी है। प्रस्ताव वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से भेजा गया है। वे 13 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। परंपरा के अनुसार, वर्तमान सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के रूप में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश करते हैं।

देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस गवई

जस्टिस गवई वरिष्ठता के क्रम में सबसे आगे हैं, जिसके चलते उनके नाम की सिफारिश की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले कानून मंत्रालय ने सीजेआई जस्टिस खन्ना से उनके उत्तराधिकारी का नाम देने की आधिकारिक अपील

की थी। जस्टिस गवई के नाम पर अगर मुहर लगती है तो वे देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे 14 मई को सीजेआई पद की शपथ ले सकते हैं। जस्टिस गवई का कार्यकाल हालांकि छह महीने का ही होगा क्योंकि वे नवंबर 2025 में रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस गवई को 24 मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था।

पिता रहे हैं बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल

जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। जस्टिस गवई के पिता दिवंगत आरएस गवई भी एक मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल रहे। जस्टिस गवई ने अपने वकालत करियर की शुरूआत साल 2003 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में बतौर एडिश्नल जज की थी।

इसके बाद साल 2005 में वे स्थायी जज नियुक्त हुए। जस्टिस गवई ने 15 वर्षों तक मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी की पीठ में अपनी सेवाएं दीं।जस्टिस गवई के नाम पर अगर मुहर लगती है तो वे देश के दूसरे अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनसे पहले जस्टिस केजी बालाकृष्णन साल 2010 में यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

ईडी ने गुरुग्राम जमीन मामले में रॉबर्ट वाड्रा से कई घंटे की पूछताछ

नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थि?त डीएलएफ लैंड डील घोटाले के मामले में लगातार दूसरे दिन बुधवार को कई घंटे पूछताछ की। रॉबर्ट वाड्रा ने पूछताछ के बाद कहा कि उन्हें सच पर भरोसा है और वे किसी भी तरह के दबाव का सामना करने के लिए तैयार हैं। राबर्ट वाड्रा के साथ आज उनकी पत्नी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को गुरुवार सुबह 11 बजे नई दिल?ली में स्थित एजेंसी के हेड क्वार्टर में पूछताछ के लिए

बुलाया है। इससे एक दिन पहले मंगलवार को ईडी के अधिकारियों ने इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से करीब छह घंटे मैराथन पूछताछ की थी। इसके बाद आज फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा से कल भी पूछताछ होगी। ईडी दफ्तर से दफ्तर से बाहर निकलते समय रॉबर्ट वाड्रा कहा, "हां, उन्होंने मुझे कल भी पूछताछ के लिए बुलाया है। वे मुझे बुलाते रहेंगे...।" रॉबर्ट वाड्रा आज मध्य दिल्ली के सुजान सिंह पार्क स्थित अपने घर से 2 किलोमीटर पैदल चलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी के मुख्यालय पहुंचे। वाड्रा ने रास्ते में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि यह मामला करीब 20 साल पुराना है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के तहत निशाना बनाया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भूमिका निभा सकते हैं भारत-ब्राजील: शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज साओ पाउलो में ब्राजील के प्रतिष्ठित कृषि व्यापार समुदाय के 27 सदस्यों से विस्तृत बातचीत की। यह वार्ता भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वसुधैव कुटुम्बकम् के दृष्टिकोण और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने की नीति के अंतर्गत आयोजित की गई। एक सरकारी प्रवक्ता ने यहां बताया कि इस संवाद में भारत और ब्राजील के बीच कृषि व्यापार को बढ़ावा देने, बेहतर उत्पादन तकनीकों का आदान-प्रदान, खाद्य प्रसंस्करण की उन्नत तकनीकों को अपनाने, बायो फ्यूल और बायो एनर्जी के उत्पादन में सहयोग, तकनीकी नवाचार और आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण जैसी संभावनाओं पर गहन चर्चा की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और ब्राजील के संयुक्त प्रयास वैश्विक खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने ब्राजील की कृषि में मशीनों के व्यापक उपयोग, विशेषकर कपास और सोयाबीन की कटाई की सराहना की और इन क्षेत्रों में सहयोग की आशा व्यक्त की। ब्राजील के चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में भारत-ब्राजील कृषि व्यापार 2-3 बिलियन डॉलर का है, जबकि इसकी क्षमता 15-20 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की है।

ब्राजील मुख्यतः उर्वरक, सोयाबीन, खाद्यान्न फसलें, चीनी, मांस और सब्जियां निर्यात करता है। ब्राजील के पूर्व कृषि मंत्री ने उल्लेख किया कि जहां आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व ब्राजील अपने कुल खाद्य पदार्थों का 30% आयात करता था।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना में बनी देश की सबसे लम्बी सुरंग

नई दिल्ली

देश की सबसे लंबी रेलवे टनल (सुरंग संख्या-8) ऋषिकेश-कर्णप्रयाग परियोजना सुरंग का बुधवार को उद्घाटन समारोह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्थानीय सांसद अनिल बलूनी की मौजूदगी में हुआ। रेल मंत्रालय के अनुसार, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना में सुरंग संख्या-8 (14.58 किलोमीटर) भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बनने जा रही है। वर्तमान में सबसे बड़ी रेल

सुरंग - उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के कटरा-बनिहाल सेक्शन पर खारी और सुंबर स्टेशनों के बीच 12.75 किलोमीटर की है। मनाली-लेह राजमार्ग पर अटल सुरंग (9.02 किलोमीटर) को सबसे लंबी सड़क सुरंग माना जाता है।

सुरंग की मुख्य विशेषताएं

इसमें 12 स्टेशन, 19 बड़े पुल, 38 छोटे पुल हैं और परियोजना की कुल लंबाई 125.20 किमी है। इसका 83 प्रतिशत हिस्सा सुरंग (104 किमी) है। 14.72 प्रतिशत हिस्सा खुले कटाव तटबंध (18.4 किमी) है। 2.21 प्रतिशत महत्वपूर्ण पुल (3.07 किमी) हैं। मुख्य सुरंग की कुल लंबाई 104 किमी है और सुरंगों की संख्या 16 है।

इस हिसाब से परियोजना की कुल सुरंग की लंबाई 213.57 किमी है। इसमें 104 किमी की 16 मुख्य सुरंग, 97.72 किमी की 12 एस्केप सुरंग और 7.05 किमी क्रॉस पैसेज शामिल हैं।

35 दवाओं के उत्पादन और बिक्री पर लगी रोक

नई दिल्ली

सरकार ने निश्चित खुराक संयोजन (एफडीसी) वाली 35 दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। बिना अनुमति बिक रहीं इन दवाओं का लोगों के सेहत पर गलत प्रभाव पड़ने के मामले सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है। इसे लेकर शीर्ष औषधि नियामक संस्था (सीडीएससीओ) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों को पत्र लिखकर गैर-अनुमोदित 35 निश्चित खुराक संयोजन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसमें दर्द निवारक, पोषण संबंधी और मधुमेह रोधी दवाएं शामिल हैं। सीडीएससीओ ने सभी औषधि नियंत्रकों से कहा है वह निश्चित खुराक संयोजन दवाओं (एफडीसी) को लाइसेंस देने की प्रक्रिया की समीक्षा करें।

सिटी बस सेवा में निजी ई-बस संचालकों को भी मिले मौका: मुख्यमंत्री

लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को नगर विकास विभाग में संचालित परियोजनाओं की समीक्षा की और भावी कार्ययोजनाओं पर विचार-विमर्श कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ ईंधन वाली बसों को नगरीय परिवहन में प्रोत्साहित करने के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। वर्तमान में 15 नगरों में 700 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो रहा है। यह सुनिश्चित किया जाए कि 15 वर्ष से अधिक समय तक किसी भी डीजल/सीएनजी बसों का उपयोग न हो। इन्हें स्क्रैप कराया जाए। इनके स्थान पर ई-बसें लाई जानी चाहिए। सिटी बस सेवा में निजी ई-बस संचालकों को भी अवसर दिया जाना चाहिए। व्यापक जनहित के दृष्टिगत

इनका किराया रेग्युलेट किया जाना चाहिए। इनके पार्किंग की जगह तय हो, रूट तय हो। इन निजी ई-बसों को समीपस्थ कस्बों से कनेक्ट किया जाए। नगरीय परिवहन में यह अच्छा प्रयास हो सकता है। नगरों में वाहन पार्किंग दिनों-दिन चुनौती बनती जा रही है। पार्किंग को मांग, स्थान और समय के अनुरूप व्यवस्थित किये जाने की आवश्यकता है। शुल्क में समरूपता होनी चाहिए। स्थानीय व्यापारियों, दुकानों, कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों आदि का मासिक पास बनाया जाए। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करायें की प्रदेश में कहीं भी पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली न होने पाए। नगरों में विज्ञापन होर्डिंग लगाए जाने में एकरूपता हो। खतरनाक होर्डिंग के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड को वरीयता दें। अवैध होर्डिंग को तत्काल हटवाएं। सभी नगरीय निकायों के लिए सुस्पष्ट नियामवली होनी चाहिए। यह निकाय की आय का अच्छा माध्यम भी बनेगा। यह सुनिश्चित करायें कि विज्ञापन होर्डिंग किसी महापुरुष की प्रतिमा/चित्र को विकृत न करता हो। नगर निगमों/नगर पालिका/नगर पंचायतों में अचल संपत्तियों के नामांतरण, पंजीयन, वसीयत आदि प्रकरणों में नगर निकायों में लिए जाने वाले शुल्क में एकरूपता नहीं है। व्यवस्था ऐसी बनाएं कि सभी नगर निकायों में एकसमान प्रक्रिया और एकसमान शुल्क प्रभावी हो।

राज्य सरकार ने सभी जिला मुख्यालय वाले नगर निकायों में स्मार्ट नगर पालिका के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना बनाई है। स्मार्ट नगर पालिकाओं में डिजिटल गवर्नेंस, वैल्यू एडेड सिटिजन सर्विस जैसे वायु और जल प्रदूषण की मॉनीटरिंग, जल भराव की समस्या की मॉनीटरिंग, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट लाइट मैनेजमेन्ट, प्रदर्शनी स्थल, ऑडिटोरियम, वेंडिंग जोन, डिजिटल लाइब्रेरी, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पों को प्रोत्साहन जैसे ईज ऑफ लिविंग के दृष्टिगत उपयोगी कार्य होंगे।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता : सीएम योगी

एजेंसी

लखनऊ । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि 1995 में गठन के बाद से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गतिविधियों, क्षेत्र और कार्य की प्रकृति में व्यापक परिवर्तन आ चुका है। बदलते समय की आवश्यकताओं के दृष्टिगत इनमें दलाव किया जाना चाहिए।

बुधवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 75 जिलों में 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन्हें 18 मंडलों पर पुनर्गठित किया जाए, साथ ही, प्रत्येक जनपद में एक-एक कार्यालय स्थापित किया जाए। जिन मंडलों में औद्योगिक गतिविधियां अधिक हैं, वहां एक से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए दौर की पर्यावरणीय चुनौतियों के समुचित समाधान के लिए बोर्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, खतरनाक कचरा, ई-वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन सेल का गठन किया जाए। इसी प्रकार, लोक शिकायत निवारण के

लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी अध्ययन हेतु, पर्यावरणीय जन-जागरूकता और प्रकाशन हेतु आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हेतु विशेष यूनिट का गठन भी किया जाना चाहिए। इससे बोर्ड की प्रभावशीलता पर सकारात्मक असर पड़ेगा। बैठक में सीएम योगी ने उद्योगों से संबंधित अनापत्ति आवेदन (सीटीओ/सीटीई) निस्तारण के समय को और कम करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि लाल, नारंगी तथा हरी श्रेणी के लिए अनापत्ति आवेदन का निस्तारण 120 दिनों में किया जा रहा है। इसे क्रमशः अभी 40, 25 और 10 दिनों में किया जाना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक तंत्र विकसित करें। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाए। बेहतर होगा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) आदि प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के दक्ष युवाओं को अच्छे पैकेज पर नियुक्ति दी जाए। इस संबंध में नियमानुसार बोर्ड स्तर पर निर्णय लिया जाना चाहिए। अनापत्ति एवं सहमति शुल्क में वर्ष 2008 के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस संबंध में बोर्ड को गहन विचार-विमर्श कर आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए।

वक्फ विरोध प्रदर्शन को लेकर ममता बनर्जी का दावा- कांग्रेस की जीती सीट पर ही भड़की हिंसा

एजेंसी

कोलकाता। वक्फ कानून में संशोधन को लेकर मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया है। ममता ने कहा कि जिस क्षेत्र में अशांति फैली, वह कांग्रेस की लोकसभा सीट का हिस्सा है और वहां की स्थिति को नियंत्रित करना कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह एक पूर्वनियोजित सांप्रदायिक हिंसा थी, जिसमें जानबूझकर उकसावे की भूमिका रही। बुधवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमाम और मोअज्जिनों की एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, ÷मालदा लोकसभा क्षेत्र में जो इलाका आता है, वहां कांग्रेस ने चुनाव जीता था। कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि वह स्थिति को संभालती लेकिन वहां जानबूझकर उकसावे के जरिए अशांति फैलाई गई। ममता ने जोर देते हुए कहा, अगर तृणमूल कांग्रेस इस हिंसा में शामिल होती तो तृणमूल के सांसदों और विधायकों पर हमले नहीं होते। उनके घरों पर हमला नहीं होता। हालांकि मुख्यमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सीमा सुरक्षा को लेकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। ममता ने यह सवाल भी उठाया कि अगर केंद्र सरकार की एजेंसियां ठीक से काम कर रही होतीं, तो सीमा पार से किसी तरह की घुसपैठ या उकसावे की कार्रवाई क्यों होती? उल्लेखनीय है कि मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। हिंसा में कई लोग घायल हुए और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी एनआईए जांच की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है।

पश्चिम बंगाल में संवैधानिक मशीनरी फेल, अपराधियों के चंगुल में ममता सरकार : मुख्तार अब्बास नकवी

नई दिल्ली। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को समाचार एजेंसी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला बोला। ममता सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि वह राज्य में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को नजरअंदाज कर रही हैं और क्रिमिनल-कम्युनल-क्रूर कारीगरों के हाथों की कठपुतली बन चुकी हैं। नकवी ने सीएम ममता बनर्जी संग इमामों की बैठक को लेकर कहा कि कुछ जगहों पर विशेषकर पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, जो चिंता का विषय है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार उन लोगों के हाथों बंधक बन चुकी है जो अपराध, सांप्रदायिकता और क्रूरता को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि सरकार उन्हीं के सम्मेलन आयोजित करती है, तो सवाल यह उठता है कि वह भरोसे का संदेश देना चाहती है या भय का। बंगाल में लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन इस बात का प्रमाण है कि वहां की संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। नकवी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर भी जुबानी हमला बोला। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद कांग्रेस की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर भी नकवी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुनबे की करतूतों को क्रांति का ताबूत बनाकर पेश करने की कोशिश कर रही है। यह जो कार्रवाई हो रही है, वह किसी राजनीतिक द्वेष का हिस्सा नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार पर आधारित वैधानिक प्रक्रिया है। कोर्ट ने पहले ही इस पर निर्देश दिए हुए हैं।

नेशनल हेराल्ड केस पर बोले अखिलेश यादवः श्वष्ठजैसी एजेंसियों को खत्म कर देना चाहिए

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद जहां देशभर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक अलग और तीखा रुख अपनाया है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'ईडी जैसी एजेंसियों को खत्म कर देना चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा,'कांग्रेस ने ही ईडी का गठन किया था। आज वे ईडी के कारण मुश्किल में हैं...आर्थिक अपराधों की जांच के लिए कई संस्थाएं हैं...ईडी जैसी एजेंसियों को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस ने ही ईडी कानून बनाया था। उस समय कई पार्टियों ने इसका विरोध किया था और कांग्रेस से कहा था कि आप ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे अंततः आपको ही परेशानी हो सकती है। महाराष्ट्र में भाजपा के खिलाफ कोई भी नेता ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का सामना करता था...मैं इतना समझता हूं कि ईडी जैसे विभाग को खत्म कर देना चाहिए। मैं कांग्रेस से भी यही मांग करने को कहूंगा। ईडी होने का मतलब है कि आप आयकर विभाग या जीएसटी जैसी अपनी संस्थाओं पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, '... यूपी का डबल इंजन एक दूसरे के पक्ष में नहीं है। एक दूसरे से टकरा रहे हैं। साथ नहीं चल रहे। आमने सामने टक्कर मार रहे हैं। पहले इंजन टक्कर मार रहे थे, अब डिब्बे भी टक्कर मार रहे हैं।

वैश्विक खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने में खास भूमिका निभा सकते हैं भारत और ब्राज़ील : शिवराज चौहान

शिवराज चौहान ने ब्राजील के कृषि व्यापार समुदाय के सदस्यों से किया विचार-विमर्श

एजेंसी

नोएडा । दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में मौसम साफ रहने के साथ-साथ तापमान भी बढ़ने लगेगा। आज सुबह के समय तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। बीते दिनों हुई आंधी व बारिश से तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आई थी। अब मौसम साफ है। सुबह से धूप खिलने के साथ मौसम सामान्य बना हुआ है। इसके चलते ही मौसम विभाग ने अब आने वाले दिनों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दो दिनों के अंदर ही अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाएगा। मौसम विभाग ने तीन दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक, 15 अप्रैल को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री बने रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक हीट

वेव के अलर्ट को जारी किया है, जिसमें 16, 17 और 18 अप्रैल शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, 16 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री बने रहने की संभावना है। वहीं, 17 अप्रैल को अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री बने रहने की संभावना जताई गई है। इसके बाद अगले दिन, 18 अप्रैल को अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री होने की संभावना जताई गई है। इन तीन दिनों के बाद मौसम विभाग के मुताबिक, हीट वेव का असर कुछ कम होता दिखाई देगा। 19 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। जबकि 20 अप्रैल को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं, 21 अप्रैल को भी अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री बने रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए इन आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ में हुई गड़बड़ी के कारण लगातार मौसम में अलग-अलग बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर तेज बारिश और हवा का सामना दिल्ली एनसीआर के लोगों को करना पड़ सकता है, जिसके बाद पारे में एक बार फिर गिरावट दर्ज की जाएगी।

आगामी दिनों में जिला संगठन के माध्यम से पार्टी चुनावों में उम्मीदवार उतारेगी : राहुल

● पार्टी के अंदर प्रोडक्टिव कम्पिटिशन होना चाहिए।

एजेंस

मोडासा। गुजरात के मोडासा से संगठन सृजन अभियान पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को 1200 से अधिक बूथ प्रमुखों को संगठन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में पार्टी जिला संगठन के माध्यम से उम्मीदवार उतारेगी और पार्टी में नई पीढ़ी को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। अरवल्ली जिले के मोडासा के स्वामीनारायण मंदिर हॉल में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ओर भाजपा पर प्रहार किया

तो दूसरी ओर गुजरात में संगठन की मजबूती से चुनाव जीतने की रणनीति पर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई राजनैतिक है, लेकिन यह विचारधारा की भी लड़ाई है। देश में दो ही विचारधारा की पार्टी है, एक कांग्रेस और दूसरा आरएसएस-भाजपा।

यदि भाजपा को हराना है तो रास्ता गुजरात से होकर जाता है। राहुल ने कहा कि काफी सालों से गुजरात में पार्टी हतोत्साहित है, इस वजह से लगता है कि यह काम मुश्किल है। इसके लिए पार्टी में बदलाव लाना होगा। पार्टी के अंदर प्रोडक्टिव कम्पिटिशन होना चाहिए। राहुल ने पार्टी की कमियां गिनाते हुए कहा कि स्थानीय नेताओं को टिकट बांटने में शामिल नहीं किया जाता है। जिले के नेताओं को पावर और जिम्मेदारी देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रभारी नेता जिले के लोगों से बातचीत कर हाईकमान को 5-6 नाम देंगे, जिसमें से जिलाध्यक्ष को चुना जाएगा। स्थानीय और जनता की समस्याओं को उठाने वाले नेताओं को पार्टी आगे बढ़ाएगी, उन्हें सशक्त बनाएगी।

जस्टिस अरुण पल्ली बने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, शपथ ली

एजेंसी

श्रीनगर। जस्टिस अरुण पल्ली को बुधवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। राजभवन में सादे लेकिन प्रभावशाली समारोह में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायपालिका और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया भी इस अवसर पर मौजूद थे। जस्टिस पल्ली के मूल हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा के वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ-साथ अधिवक्ता, परिवार और मित्र भी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस समारोह में शामिल हुए।

मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने गठित की समिति

एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसक घटनाओं को गंभीरता ले लिया है। महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने इन घटनाओं का स्वत-संज्ञान लेते हुए इसकी जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की है। एनसीडब्ल्यू ने बुधवार को एक बयान में बताया कि मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान के मंदिरपारा इलाके में सांप्रदायिक अशांति के दौरान कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं की खबरें सामने आई हैं। हिंसा के कारण सैकड़ों महिलाओं को पलायन करना पड़ा, जिनमें से कई को सुरक्षा की तलाश में भागीरथी नदी पार करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनको पास के मालदा जिले में शरण लेनी पड़ी। ये महिलाएं

अपने घरों से दूर हो गई हैं, डर और अनिश्चितता में जी रही हैं। विजया रहाटकर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी, लोगों से मिलेंगी और स्थिति का आकलन करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगी। इस जांच समिति में एनसीडब्ल्यू की सदस्य डॉ अर्चना मजूमदार और एनसीडब्ल्यू की उप सचिव डॉ शिवानी डे भी शामिल होंगी।

लोगों को जोड़ने वाली कर्म की राजनीति से ही सभी की भलाई संभव : बसपा अध्यक्ष मायावती

इस बैठक में दोनों राज्यों में पार्टी संगठन की समीक्षा की गई।

एजेंसी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में दोनों राज्यों में पार्टी संगठन की समीक्षा की गई। बैठक में बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार सर्वसमाज के करोड़ों गरीब बहुजनों के समुचित हित, कल्याण एवं विकास के हिसाब से कार्य न करके, सपा सरकार की तरह ही, केवल कुछ क्षेत्र व समूह विशेष के लोगों के लिए ही समर्पित

है और वैसा ही दिखना भी चाहती है, जिससे यूपी का बहु-अपेक्षित व अति-प्रतीक्षित विकास प्रभावित हो रहा है। जबकि, बसपा की सभी चारों सरकारों में सर्वसमाज को न्याय दिलाने और विकास में उचित भागीदार बनाने के साथ-साथ कानून द्वारा कानून का राज सख्ती से स्थापित करके खासकर करोड़ों दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, किसानों और बेरोजगारों आदि अन्य उपेक्षितों के हितों की रक्षा, सुरक्षा व उन्हें न्याय दिलाने पर विशेष बल दिया गया था, जिससे यहां हर तरफ अमन चैन का माहौल था।

इसलिए यूपी और उत्तराखंड भाजपा सरकार को भी धर्म को कर्म के बजाय कर्म को धर्म मानकर कार्य करने का सही संवैधानिक दायित्व निभाना जरूरी है, जिसमें ही जन व देशहित पूरी तरह से निहित है। उन्होंने कहा कि वैसे तो बहुजनों में भी खासकर दलित समाज के वोटों के स्वार्थ की खातिर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती आदि पर याद करने की होड़ सी लगी रही है, किंतु ऐसे समय में भी उनकी प्रतिमाओं का अनादर व उनके अनुयायियों को प्रताड़ित करने और हत्या आदि की वारदातें यह साबित करती हैं कि इन बीएसपी विरोधी पार्टियों में बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर के प्रति आदर-सम्मान, निष्ठा व ईमानदारी राजनीति से प्रेरित छलावा है।

मुर्शिदाबाद में फिर भड़की आग

उपाध्यक्ष के भाई की दुकान में उपद्रवियों ने लगाई आग, वक्फ कानून के विरोध में तनाव बरकरार

एजेंसी

धुलियान (मुर्शिदाबाद)। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान इलाके में तनाव एक बार फिर सिर चढ़कर बोल रहा है। वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा ने बुधवार को नया रूप ले लिया, जब उपद्रवियों ने नगर पालिका के उपाध्यक्ष सुमित सहर के बड़े भाई प्रबीर सहर की दुकान को आग के हवाले कर दिया। वार्ड नंबर 5 में स्थित यह दुकान एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान थी, जिसे पूरी तरह से जला दिया गया। सहर परिवार का कहना है कि जब वे सुबह दुकान पहुंचे, तो वहां सिर्फ राख और तबाही बाकी थी। उनका घर घटनास्थल से

करीब तीन किलोमीटर दूर है।

प्रश्नों के घेरे में सुरक्षा व्यवस्थाः ुलियान में पहले से ही केंद्रीय बलों की गश्त जारी है, स्थानीय पुलिस भी निगरानी में लगी है – फिर भी इस तरह की घटना कैसे हुई? ये सवाल अब आम लोगों के साथ प्रशासन के सामने भी खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश दोनों साफ नज़र आ रहे हैं। एक ओर जहां व्यापारी वर्ग दहशत में है, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल के नेताओं पर सीधा निशाना साधे जाने की आशंका से राजनीतिक तापमान भी चढ़ गया है।

क्या कहती है प्रशासनिक तैयारी?

धुलियान नगर पालिका क्षेत्र पहले भी हिंसा की चपेट में आ चुका है। लगातार तनाव के बीच प्रशासन की यह कोशिश है कि हालात को नियंत्रण में रखा जाए, लेकिन बार-बार सामने आती ऐसी घटनाएं संकेत देती हैं कि कहीं न कहीं कुछ चूक रह जाती है।

कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोली भाजपा, गांधी परिवार देश के कानून से ऊपर नहीं

एजेंसी

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट के बाद राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस देशभर में प्रदर्शन कर रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ने पलटवार करते हुए कहा कि गांधी परिवार ने गैरकानूनी तरीके से हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा किया है। कांग्रेस को धरना देने का अधिकार है, लेकिन जमीन लूटने का नहीं। देश के कानून से कांग्रेस परिवार ऊपर नहीं है। बुधवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है और देशभर में धरना देने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार उन्हें (कांग्रेस को) नहीं है। नेशनल हेराल्ड 1937 में शुरू किया गया था। इसमें 5 हजार शेयर होल्डर्स थे। ये नेहरू खानदान की जागीर कभी नहीं रही है। 2008 में नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया, क्योंकि वो चल नहीं रह था। उसके बाद कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को पब्लिश करने वाली एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को 90 करोड़ रुपये दिए थे। गांधी परिवार का पूरा आचरण भ्रष्टाचार का रहा है। शेयर की हेराफेरी करो और संपत्ति बनाओ, जबकि ये सारी संपत्ति सरकार द्वारा दी हुई थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद पार्टी फंड को एक निजी संस्था को दे दिया, जो प्रतिबंधित है।

महाराष्ट्र के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात

एजेंसी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स हैंडल पर मुलाकात की तस्वीरें साझा की हैं। वहीं राज्यपाल ने एक्स पोस्ट में कहा कि आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलकर प्रसन्नता हुई।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हुई कांग्रेस-राजद की बैठक, 17 अप्रैल को पटना में होगी आगे की चर्चा

नई दिल्ली। इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं।इसी संदर्भ में दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाग लिया। आगे की चुनावी रणनीति को लेकर अब 17 अप्रैल को पटना में बैठक बुलाई गई है जिसमें विपक्ष के अन्य दलों के प्रतिनिधियों के भी भाग लेने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के आवास पर हुई बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार शामिल हुए। वहीं, राजद सांसद मनोज झा भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि आज की बैठक में महागठबंधन की मजबूत बनाए जाने पर विचार किया गया। बिहार में इस बार निश्चित तौर पर बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में बिहार की जनता को हम एक सशक्त, सकारात्मक, न्यायप्रिय व कल्याणकारी विकल्प देंगे। युवा, किसान-मज़दूर, महिलाएँ, समाज के पिछड़े, अति पिछड़े व अन्य सभी वर्गों के लोग बिहार में महागठबंधन की सरकार चाहते हैं।

देश में इस साल 105 प्रतिशत हो सकती है मानसूनी बारिशः आईएमडी

नई दिल्ली। देश में इस वर्ष अच्छी बारिश के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया कि जून से सितंबर 2025 तक मानसून बेहतर रहेगा। इस दौरान 105 प्रतिशत मानसूनी बारिश हो सकती है। यानी इस साल देश में 87 सेंटीमीटर बारिश होने की उम्मीद है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम. रविचंद्रन ने मौसम विभाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जून से सितंबर तक वर्षा सामान्य से अधिक रहेगी। इस साल भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के दौरान अल नीनो स्थितियां विकसित होने की संभावना नहीं हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, केवल उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों को छोड़ कर सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। यानी देश के 80 प्रतिशत जगहों में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। सिर्फ नॉर्थवेस्ट, ईस्ट, उत्तर- ईस्टर्न इंडिया में सामान्य से नीचे बारिश होने के आसार हैं। रविचंद्रन ने बताया कि पिछले तीन महीने यानी जनवरी से मार्च 2025 के दौरान उत्तरी गोलार्ध और यूरेशिया में बर्फ की चादर सामान्य से नीचे थी। उत्तरी गोलार्ध के साथ-साथ यूरेशिया में सर्दियों और वसंत में बर्फ की चादर के विस्तार का भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा के साथ एक सामान्य विपरीत संबंध है।

जलियांवाला बाग पर अक्षय कुमार बोले- 'इतिहास की किताबों ने जो सिखाया, वही जानता हूं'

नई दिल्ली। 13 अप्रैल 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड पर बनी अभिनेता अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सिनेमाघरों से ज्यादा दूर नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित फिल्म के प्रीमियर में राजनीतिक हस्तियों के साथ अभिनेता अक्षय कुमार और आर माधवन भी शामिल हुए। इस मौके पर कुमार ने कहा कि 'इतिहास की किताबों ने जो सिखाया, वही जानता हूं। अभिनेता ने कहा, जब जलियांवाला बाग की बात आई, तो उन्हें केवल वही पता था, जो इतिहास की किताबों ने उन्हें सिखाया था। 'केसरीः चैप्टर 2' के प्रीमियर में कई प्रमुख राजनीतिक नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अक्षय कुमार, आर. माधवन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए। प्रीमियर के बारे में अक्षय ने कहा, हम बहुत आभारी हैं कि हरदीप सर ने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन और मेजबानी की।

शिक्षा से संवेदना और जीवन मूल्यों का विकास आवश्यकः डॉ जितेन्द्र सिंह

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत विकास परिषद, दिल्ली प्रान्त (उत्तर) ने प्रधानमंत्री संग्रहालय, नई दिल्ली में सामाजिक समरसता में शिक्षा एवं संस्कारों की भूमिका विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी के मुख्यातिथि प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेन्द्र सिंह ने समाज निर्माण में शिक्षा एवं संस्कारों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि आज का जो विषय है, यह किसी को सिखाया नहीं जा सकता। शिक्षा केवल लोगों में भावना उत्पन्न कर सकती है। शिक्षा प्राप्त करने से यह आवश्यक नहीं कि समरसता और संस्कार आ जाएं। केंद्रीय मंत्री ने कई महापुरुषों के वक्तव्यों को साझा करते हुए भारत की ताकत पर जोर दिया। देश के बंटवारे को लेकर कहा कि देश के पढ़े-लिखे लोगों ने ही देश का बंटवारा कराया। वहीं नई शिक्षा नीति को लेकर कहा कि भविष्य में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पुरानी शिक्षा को लेकर कहा कि मुझे

यह हैरानी हुई कि लोग इसे कैसे झेलते रहे। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। बीते दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जिनका आज के विषय से गहरा नाता है। अंबेडकर ने संविधान में सभी में एकता की भावना उत्पन्न करने के लिए इस विषय को जोड़ा। उन्होंने आगे भारतीय संस्कृति पर जोर देते हुए कहा कि एक हैं तो सेफ हैं यह बिल्कुल सही कहा जा रहा है। वहीं वक्फ कानून को लेकर बंगाल में हुई हिंसा पर कहा कि कानून का विरोध हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार की हिंसा हुई वह गलत है। विशिष्ट अतिथि कर्नल सिंह जी, राष्ट्रीय संयोजक (संपर्क- भारत विकास परिषद) एवं पूर्व निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि सामाजिक समरसता के लिए केवल शिक्षा नहीं, बल्कि लोगों की सोच में भी बदलाव की आवश्यकता है। वोटबैंक की राजनीति के लिए लोगों को बहकाया जा रहा है। आज के युवाओं को अपने रोल मॉडल को सही ढंग से चुनना होगा। प्रो. बलराम पाणी जी, डीन ऑफ कॉलेजेस, दिल्ली विश्वविद्यालय ने शिक्षा प्रणाली की वर्तमान चुनौतियों की चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ युवाओं को अपने संस्कारों पर भी काम करना होगा। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन ने परिषद के उद्देश्य, कार्यपद्धति एवं सेवा-संस्कार आधारित दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हाल ही में अंबेडकर जयंती मनाई गई। उन्होंने लोगों को शक्ति दी। भारत विकास परिषद के अंदर सेवा की भावना है।

डीआरआई ने आईजीआई एयरपोर्ट पर 7.56 किलोग्राम कोकीन जब्त की

एजेंसी

नई दिल्ली। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर करीब 75.6 करोड़ रुपये मूल्य की 7.56 किलोग्राम कोकीन जब्त करने के साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अभियान में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर डीआरआई ने 14 अप्रैल को इंदिरा गांधी अंतरराष?ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर दुबई से आने वाले एक भारतीय नागरिक को रोका। यात्री के बैगेज की गहन जांच के बाद पांच खाली हैंडबैग यानी पर्स पाए गए। इन पांच बैगों की भीतरी परतों को काटने पर 7.56 किलोग्राम वजन के सफेद पाउडर के 10 पैकेट छिपे पाए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने इस पाउडर को जांच के लिए भेजा तो कोकीन की पुष्टि हुई। बरामद कोकीन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 75.6 करोड़ रुपये कीमत आंकी गई है। इसके बाद पकड़े गए व्यक्ति को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। डीआरआई तस्करी ऑपरेशन में शामिल किसी भी संभावित नेटवर्क की पहचान करने के लिए आगे की जांच कर रहा है।

आईएएस अधिकारियों के विकास कार्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगेः राष्ट्रपति

एजेंसी

नई दिल्ली। वर्तमान में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में कार्यरत 2023 बैच के आईएएस अधिकारियों के एक समूह ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने आईएएस अधिकारियों से कहा कि स्थानीय और राज्य स्तर पर उनके द्वारा किए गए विकास और जनकल्याण के कार्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे। राष्ट्रपति ने आईएएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे असाधारण दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से आईएएस अधिकारी बने हैं। इससे उनके व्यक्तिगत जीवन में भी बड़ा बदलाव आया है। अब और भी अधिक दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ उन्हें अनगिनत लोगों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने का अवसर मिला है। उनकी सेवा और अधिकार का क्षेत्र इतना व्यापक है कि वे अपनी पहली पोस्टिंग में ही कई साथी नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। राष्ट्रपति ने उन्हें

वंचितों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी सलाह दी कि वे अपने करियर के दौरान कुछ समय बाद पोस्टिंग वाले स्थानों का दौरा करें और अपने काम के दूरगामी परिणाम देखें। राष्ट्रपति ने कहा कि अधिकारियों को सिविल सेवकों के अधिकारों और कर्तव्यों को ध्यान में रखना चाहिए। एक लोकसेवक के कर्तव्य उसकी जिम्मेदारियां हैं और उसके अधिकार उन कर्तव्यों को पूरा करने का साधन हैं। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से कहा कि उनके करियर की असली कहानी उनके काम से बनेगी, न कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने से। उनकी असली सामाजिक संपत्ति उनके अच्छे काम से तय होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लोकसेवक को ईमानदारी और उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का हम सभी सामना कर रहे हैं।

गडकरी ने अधिकारियों को सड़क इंजीनियरिंग की खामियों को सुधारने की दी हिदायत

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत मंडपम में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हर साल एक लाख 80 हजार लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को सड़क इंजीनियरिंग की खामियों को सुधारने की हिदायत देते हुए कहा कि ऐसा करने से कम से कम 40 हजार लोगों की जान प्रतिवर्ष बचेगी। केंद्रीय मंत्री गडकरी राजमार्ग अवसंरचना के विकास, रखरखाव और नवाचार में नए मानक स्थापित करने वाले विजेताओं को राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार-2023 प्रदान करने के बाद संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी उपस्थित थे। गडकरी ने अधिकारियों से सवाल किया कि सड़क हादसों में लोगों की जान बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सड़क इंजीनियरिंग में कोई कमी है तो हमें उसे सुधारें। उन्होंने हादसों में लोगों की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि सड़क हादसों 18-34 साल के 60 प्रतिशत युवा जान गंवा रहे हैं। उन्होंने

अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ सड़क इंजीनियरिंग की खामियों को सुधारने की हिदायत देते हुए ऐसा करने से कम से कम 40 हजार लोगों की जान प्रतिवर्ष बचेगी। उन्होंने प्रतिदिन सड़क निर्माण का औसत लक्ष्य बढ़ाने की सलाह देते हुए कहा कि इस लक्ष्य का हासिल करने के लिए सकारात्मकता से काम करना होगा। गडकरी ने अधिकारियों को पारिस्थितिकी पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हम कई बातों में सुधार करके विश्व के नंबर एक नेशनल हाईवे क्वालिटी नेटवर्क बन सकते हैं। हम अभी सबसे बड़ा रोड नेकवर्क हैं। अभी देश में 62 लाख किमी सड़क है और उसमें से 40 प्रतिशत नेशनल हाईवे में है। गडकरी ने कहा कि पिछले 11 साल में किसी अधिकारी पर कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई काम करने का दबाव नहीं बनाया। सड़क बनाने के कार्य को लाभ का विषय बताते हुए उन्होंने कहा कि यदि हम अधिक रोड नहीं बनाएंगे तो एनएचएआई और मंत्रालय का नुकसान करेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़क बनाने पर टोल से आमदनी हो होगी। गडकरी ने सड़क निर्माण परियोजना के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन (सीओएस) और समय विस्तार (ईओटी) दोनों के अनुरोध संबंधी सीओएस ईओटी प्रस्ताव को लेकर कहा कि अधिकारियों को इसको लटकाने के बजाय शीघ्र निर्णय करना चाहिए।

वक्फ अधिनियम 2025 से वक्फ संपत्तियों को लाभ पहुंचने के बजाय नुकसान होने का खतराः जमीअत उलमा-ए-हिंद

एजेंसी

नई दिल्ली। जमीअत उलमा-ए-हिंद द्वारा दिल्ली कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रख्यात कानूनी विशेषज्ञों, विद्वानों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक नेताओं ने एकमत होकर वक्फ अधिनियम 2025 की कई कमियों को उजागर करते हुए इसे वक्फ संपत्तियों के लिए खतरा बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वक्फ की सुरक्षा न केवल कानूनी बल्कि धार्मिक, नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। विशेषज्ञों ने इस कानून को उपासना स्थल अधिनियम 1991 को कमजोर और अप्रभावी बनाने वाला भी बताया। अपने उद्घाटन भाषण में जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि जमीअत उलमा-ए-हिंद ने आजादी से पहले और बाद में वक्फ की रक्षा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। जमीअत की सिफारिशों को 1937 के शरीयत एप्लीकेशन एक्ट और बाद में 1954 और 1995 के वक्फ अधिनियमों में शामिल किया गया, लेकिन वर्तमान सरकार ने किसी भी धार्मिक या कानूनी संस्था की राय को ध्यान में नहीं रखा है। मौलाना मदनी ने कहा कि मौजूदा मसौदा कानून वक्फ की भावना और उसके उद्देश्यों को कमजोर करता है। इसलिए जरूरी है कि न सिर्फ कानूनी और संवैधानिक स्तर पर इसका विरोध किया जाए, बल्कि जनता में जागरूकता भी पैदा की जाए ताकि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वक्फ विशेषज्ञ और पूर्व आईआरएस अधिकारी सैयद महमूद अख्तर ने कहा कि नए कानून का ढांचा दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसा है, जिसमें शरिया सिद्धांतों की कोई झलक नहीं है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पूर्व सदस्य एम. इकबाल ए शेख ने कहा कि धारा 40 और धारा 83 के जरिए वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों का कानूनी दर्जा खत्म करने की कोशिश की गई है। दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन एडवोकेट पीरजादा फरीद अहमद निजामी ने कहा कि धारा-3 में पांच साल के मुसलमान की शर्त और धारा 3डी में पुरातात्विक स्थलों के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों से वक्फ का दर्जा खत्म करने जैसे बिंदु इस्लामी सिद्धांतों के विपरीत हैं।

वक्फ कानून को लेकर हिंसा : विहिप ने राज्य सरकार से जिहादियों के हमले रोकने की मांग की

कोलकाता। वक्फ संशोधन कानून के विरोध को लेकर पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला है। विहिप ने इन हमलों को तुरंत रोकने और पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। सिलीगुड़ी में संवाददाताओं से बात करते हुए विहिप के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने ममता बनर्जी सरकार के दो मंत्रियों फिरहाद हकीम और सिद्दीकुल्लाह चौधरी के बयानों को उकसाने वाला और असंवेदनशील बताया। उन्होंने दावा किया कि मुर्शिदाबाद जिले के धूलियान इलाके से कई बंगाली हिंदू जान बचाकर पास के मालदा जिले में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने इस घटना की तुलना जम्मू-कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन से की। विहिप नेता ने कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध के दौरान सिलीगुड़ी या राज्य के अन्य हिस्सों में कानून-व्यवस्था की स्थिति और न बिगड़े। सरकार हिंसा को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए, पीड़ितों को सुरक्षा और मुआवजा दे तथा हमलावरों और भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे।

पीएम मोदी की डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन से बातचीत, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ वैश्विक विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इसकी जानकारी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन से बात करके खुशी हुई। भारत-डेनमार्क ग्रीन स्ट्रैटेजिक साझेदारी के लिए अपने मजबूत समर्थन और हमारे लोगों के लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की पुष्टि की। हमने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह इस वर्ष के अंत में नॉर्वे में आयोजित होने वाले तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और उस समय प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन के साथ बैठक में मुलाकात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि साल 2020 में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत के बाद से दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आदान-प्रदान को याद करते हुए दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के विस्तार का उल्लेख किया, जिसने भारत में डेनमार्क के

निवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई हैं ताकि ग्रीन ट्रांजिशन में योगदान दिया जा सके। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। बताते चलें कि भारत और डेनमार्क के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोग भरे संबंध रहे हैं। दोनों देश 1949 से राजनयिक संबंध साझा करते हैं। भारत-डेनमार्क को एक विश्वसनीय भागीदार मानता है। दोनों देशों के बीच हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास जैसे क्षेत्रों में विशेष भागीदारी है। खास बात यह है कि दोनों देश भारत-डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2020 के तहत सहयोग करते हैं। यह पर्यावरण, तकनीक और व्यापार पर केंद्रित है। डेनमार्क की कई कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। जबकि, भारत की आईटी और फार्मा से जुड़ी कंपनियां डेनमार्क में निवेश कर रही हैं। यह दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने में अहम योगदानकर्ता भी हैं।

ईडी ने की रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, भाजपा ने कहा- कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं

एजेंसी

नई दिल्ली। हरियाणा जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ के लिए बुलाया। राबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे और उनसे पूछताछ की गई । इस प्रकरण पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने निशाना साधते हुए कहा कि कानून से कोई ऊपर नहीं है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने एक्स प्लेटफार्म पर इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भूमि माफिया रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था। यह हरियाणा में हुए भूमि घोटाले से संबंधित है। इसे शिकोहपुर भूमि स्कैम के नाम से जाना जाता है। जहां 24 घंटे के भीतर, मुख्यमंत्री ने शक्तियों का दुरुपयोग कर, रॉबर्ट वाड्रा द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व वाली एक कंपनी को एक लाइसेंस दिया गया था। आज जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो यह कानून के शासन की शक्ति के बारे में बहुत कुछ कहता है और यह एक मजबूत संदेश भेजा गया है कि कोई भी देश के कानून के ऊपर नहीं है, खासकर झूठे गांधी परिवार से, जो

दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मामला 1 सितंबर, 2018 को दर्ज किया गया था। सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर गुड़गांव के खेरकी दौला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शर्मा का आरोप था कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया है। इस मामले में हुड्डा को भी आरोपी बनाया गया है। इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 120, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

नेशनल हेराल्ड मामला :ईडी ने राहुल-सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा के खिलाफ दायर किया आरोपपत्र, 25 अप्रैल को सुनवाई

एजेंसी

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने इस मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर ईडी के आरोपपत्र में सुमन दुबे और अन्य के नाम भी शामिल हैं। अदालत ने मामले में संज्ञान पर बहस के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले ईडी ने इस मामले से जुड़ी संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। राज्यसभा सांसद एवं दिग्गज कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे बदले की राजनीति बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म %एक्स% पर लिखा, ÷नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहनकर सरकार प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा। राजस्थान के

पूर्व मुख्यमंत्री एवं दिग्गज कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला बताया। उन्होंने %एक्स% पर लिखा, ÷मोदी सरकार की एजेंसी ईडी द्वारा कांग्रेस पार्टी और नेशनल हेराल्ड की 661 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कब्जे में लेने की कार्रवाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है। भाजपा सरकार की मंशा है कि ऐसे प्रयासों से वह धीरे-धीरे कांग्रेस को आर्थिक रूप से अक्षम बना दे। लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग के जरिए कांग्रेस के बैंक खातों को सील कर ऐसा प्रयास किया गया था। पहले आईटी और अब ईडी की यह कार्रवाई निंदनीय है। उन्होंने लिखा, नेशनल हेराल्ड केस को अब पांच साल से भी अधिक का समय हो गया है। ईडी कांग्रेस के खिलाफ तो गैर-कानूनी रूप से कार्रवाई कर रही है, वहीं भाजपा को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड्स में साफ तौर पर कंपनियों से अवैध वसूली के सबूत मिले, परंतु ईडी ने किसी भाजपा नेता को एक नोटिस तक नहीं दिया। इसी प्रकार रॉबर्ट वाड्रा को बार-बार पूछताछ के लिए बुलाकर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है।

गुरुग्राम के निजी अस्पताल में वेंटीलेटर पर हुआ एयर होस्टेस से दुष्कर्म, अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

गुरुग्राम। सदर थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन एयर होस्टेस से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वेंटिलेटर पर अचेत अवस्था में दुष्कर्म करने का आरोप अस्पताल के एक कर्मचारी पर लगा है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करपूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि पीड़ित महिला ने अपने लीगल एडवाइजर की उपस्थिति में सदर थाना पुलिस में शिकायत दी। सदर थाना पुलिस में दी शिकायत में 46 साल की महिला ने कहा कि वह एक एयरलाइंस में बतौर एयर होस्टेस नौकरी करती है और गुरुग्राम में ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी। यहां एक होटल में ठहरी थी। इस दौरान पानी में डूबने से उसकी तबियत खराब हो गई। इसके बाद

उसे 6 अप्रैल 2025 को उसके पति ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला ने शिकायत में कहा कि उसके 6 अप्रैल को वेंटिलेटर पर रहने के दौरान कक्ष में उसके साथ अस्पताल के किसी कर्मचारी ने दुष्कर्म किया। अस्पताल से 13 अप्रैल को डिस्चार्ज होने के बाद पीड़ित महिला ने अपने पति को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। महिला ने लीगल एडवाइजर की मौजूदगी में पुलिस को अपने बयान दर्ज करवाए। इस मामले में पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही आरोपित की पहचान करके गिरफ्तार किया जाएगा। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

संपादक की कलम से

समय से पहले आई खूबसूरती से क्यों भयभीत हैं पहाड़ के लोग

अगर पहाड़ों का सौंदर्य,तापमान, वर्षीय,बर्फ,बुरांश और प्राकृतिक चक्र बनाए रखना है तो प्रकृति का संरक्षण करना होगा, अंधाधुंध फैलते कांक्रीट के जंगल की रफ्तार थामनी होगी और पहाड़ों को रौंदती मोटर गाड़ियों की संख्या को नियंत्रित करना होगा वरना पहाड़ और मैदान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा।

हिमाचल प्रदेश या पूरे हिमालय क्षेत्र में सौंदर्य के प्रतीक से इन दिनों क्यों भयभीत है लोग? क्यों उन्हें यह सुंदरता रास नहीं आ रही? खूबसूरती से क्यों नाखुश है पर्वतीय इलाकों के रहवासी और प्राकृतिक सौंदर्य के उपासक क्यों नहीं चाहते असमय प्रकृति की नेमत? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमें केवल पर्वतीय इलाकों के जानकार ही दे सकते हैं। आखिर, कोई तो बात होगी जिसके फलस्वरूप यहां के लोगों को प्राकृतिक सुंदरता रास नहीं आ रही?

हम बात कर रहे हैं कि पर्वतीय राज्यों के एक सुंदर वरदान की जिसका नाम है - बुरांश। बुरांश का पेड़ और इसके फूल हिमाचल सहित देश के तमाम पर्वतीय राज्यों के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक संस्कारों से जुड़े हैं। बुरांश न केवल खूबसूरत है बल्कि सेहत की अनेक नेमतों से परिपूर्ण भी है। यह अर्थव्यवस्था का भी एक अनिवार्य हिस्सा है। बुरांश के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि आईआईटी मंडी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नालॉजी (आईसीजीईबी) के शोधकताओं ने बुरांश की पंखुड़ियों में मौजूद फाइटोकेमिकल्स की पहचान की है जो कोविड-19 वायरस को रोक सकते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि बुरांश के फूल में एंटीवायरल के गुण होते हैं, जो सार्स-सीओवी 2 से संक्रमित कोशिकाओं के इलाज में मदद कर सकते हैं। कुछ शोधों में यह भी पाया गया है कि बुरांश के रस का सेवन दिल और लिवर के लिए फायदेमंद हो सकता है।

लेकिन हिमालय को मिला प्रकृति का यही उपहार यहां खतरे का संकेत दे रहा है। पिछले कुछ सालों से यह फूल समय से पहले खिलने लगा है और यही पर्वतीय लोगों के साथ-साथ वैज्ञानिकों के लिए भी चिंता का सबब है। बुरांश का समय से पहले खिलना बर्फबारी कम होने का संकेत है और कम वर्षा का भी। शिमला या इस जैसे तमाम पर्यटन स्थलों का सौंदर्य और आर्थिक प्रगति वहां होने वाले हिमपात पर निर्भर है। बीते कुछ सालों में न केवल शिमला सहित अधिकतर पर्वतीय इलाकों की सर्दी कम हुई है बल्कि बर्फबारी के दिन भी कम होते जा रहे हैं। पहले शिमला शहर में ही जमकर बर्फ गिरती थी लेकिन अब बर्फबारी कुफरी, ठियोग और नारकंडा की ओर खिसकते जा रही है। इससे पर्यटन पर भी असर पड़ रहा है। इस समस्या को विकराल बनाने में पहाड़ों का सीना चीरकर दौड़ रहे हजारों वाहनों ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस सबसे, मौसम बदल रहा है और इसलिए बुरांश भी समय से पहले खिलने लगा है।

'डाउन टू अर्थ' पत्रिका में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक तापमान, वर्षा और बफबारी में आए बदलावों के प्रति बुरांश की संवेदनशीलता और प्रतिक्रियाओं ने चिंता बढ़ा दी है। फूलों के खिलने के समय में बदलाव के लिए काफी हद तक बढ़ते हुए वैश्विक तापमान को जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके फलस्वरूप बदल रहे मौसम के तेवरों का नुकसान बुरांश के फूलों को उठाना पड़ रहा है। मसलन बारिश की कमी के कारण इनमें रसीलेपन का अभाव हो जाता है। बुरांश के फूलों के फूलने की प्रक्रिया को समझे तो सामान्य रूप से जनवरी से फरवरी माह में वे कलियों के रूप में रहते हैं। चूंकि उस समय तापमान बहुत कम होता है और बहुत कम तापमान में कलियां खराब न हो जाए, इसके लिए प्राकृतिक तौर पर पंखुड़ियां सुरक्षा घेरे के रूप में कलियों को बाहर से ढंके रहती हैं। वे तभी हटती हैं, जब तापमान 20 से 25 डिग्री पर पहुंच जाता है। अनुकूल तापमान पाकर पेड़ का आंतरिक सूचना तंत्र (डीएनए) कोशिकाओं को संकेत भेजता है और फूलों के फूलने की प्रक्रिया के लिए हार्मोन्स सक्रिय हो जाते हैं।

यदि समय से पहले ही तापमान अधिक हो जाता है तो फूल के विकास पर असर पड़ता है और उसके रंग-रूप से लेकर आर्थिक और स्वास्थ्यप्रद गुणों पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा, अगर ये फूल समय से पहले यानी सर्दियों के अंत में ही खिलने लगते हैं तो उस समय मधुमक्खियां या परागण करने वाले कीड़े सक्रिय नहीं होते इसलिए परागण पूरी तरह नहीं हो पाता, जिससे पौधों के बीज या फल विकसित नहीं हो पाते। तापमान में उतार-चढ़ाव से पहले से खिले फूल मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं।

बुरांश के फूलों के जल्दी खिलने का असर पारिस्थितिकी तंत्र पर भी पड़ता है। दरअसल, बुरांश के फूलों पर कई पक्षी, कीड़े और अन्य जीव आश्रित होते हैं।

यदि फूल समय से पहले या अनियमित रूप से खिलते हैं, तो यह खाद्य श्रृंखला गड़बड़ा जाती है। बुरांश के फूलों का उपयोग रस और शरबत आदि बनाने में होता है। अनियमित फूलों की वजह से इनमें रस कम बनता है और किसानों और स्थानीय लोगों की कमाई भी प्रभावित होती है।

प्रीमेच्योर डिलीवरी से शिशु के दिमागी विकास पर क्या असर पड़ता है? डॉक्टर से जानें

समय पूर्व प्रसव यानी प्रीमेच्योर डिलीवरी. आमतौर पर 37 सप्ताह से पहले जन्म लेने वाले बच्चों को प्रीमेच्योर कहा जाता है. गर्भावस्था का समय पूरा होने से पहले बच्चे का जन्म होने से बच्चे में कई तरह के विकार या समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे बच्चों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है. कई बार ऐसे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है. इसके कारण ऐसे बच्चे अक्सर बीमारी की चपेट में आते रहते हैं. प्रीमेच्योर बच्चों को देखभाल और खानपान के जरिए पूर्ण स्वस्थ किया जा सकता है.

महिला को यदि डायबिटीज है या गर्भावस्था के दौरान हो जाती है. ऐसी स्थिति में प्रीमेच्योर डिलीवरी की आशंका बढ़ जाती है. इसके अलावा हाई बीपी होने के कारण भी इसकी आशंका बनी रहती है. इसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी कहते हैं. इसके अलावा महिला को किडनी संबंधी रोग होने के कारण भी प्रीमेच्योर डिलीवरी की आशंका होती है. इसके अलावा यूटीआई, गर्भाशय का संक्रमण, एक से ज्यादा बच्चे होना. गर्भावस्था के दौरान घूम्रपान और शराब का सेवन करना. पोषक तत्वों की कमी भी प्रीमेच्योर डिलीवरी की आशंका बनती है.

नवजात पर प्रभाव

प्रीमेच्योर डिलीवरी में बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. प्रीमेच्योर होने के कारण बच्चे का दिल और दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं. इसके अलावा बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होती है. ऐसे बच्चों को न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती है. उन्हें भूलने की समस्या और पढ़ाई में कमजोर रहने की आशंका रहती है. इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण कई तरह की गंभीर बीमारियां घेर सकती हैं. ऐसे बच्चे अकसर बीमार रहते हैं. बीमारी के कारण वह अपनी पढ़ाई औरकरियर पर भी पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते.

ये है निदान

प्रीमेच्योर बच्चों को खास देखभाल और पोषण की जरूरत होती है. डॉक्टर ऐसेबच्चों को खास डाइट देने की सलाह देते हैं. ऐसे बच्चों को आयरन, ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन डी और प्रोटीन से भरपूर आहार देना चाहिए. इससे बच्चे का ब्रेन फंक्शन बेहतर होता है और सीखने पढ़ने की क्षमता का विकास होता है।

तमिलनाडु में भाजपा परचम फहराने को तत्पर

- ललित गर्ग -

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही है, लेकिन अब भाजपा दक्षिण में अपनी जड़ों को न केवल मजबूत करना चाहती है बल्कि दक्षिण के राज्यों में सत्ता पर काबिज भी होना चाहती है। तमिलनाडु में अगले वर्ष अप्रैल-2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) ने 2026 के विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को अपनी महत्वपूर्ण चैन्नई यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अहम राजनीतिक गठबंधन का ऐलान करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य में एनडीए एडप्पादी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गठबंधन का चेहरा होंगे। तमिलनाडु की भाजपा में भी एक बड़ा बदलाव सामने आया है और भाजपा की तमिलनाडु इकाई की कमान नैनार नागेंद्रन को मिल गई है। भाजपा की राजनीतिक यात्रा में 2026 का तमिलनाडु चुनाव मील का पत्थर साबित होगा, वर्षों की प्यास को बुझायेगा, कमल खिलायेगा।

यह बात तो जगजाहिर है कि दक्षिण में हिन्दू मन्दिरों एवं संस्कृति का वर्चस्व होते हुए भी भाजपा अब तक अपनी जमीन मजबूत नहीं कर पाई है, जबकि केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु हो, भाजपा अपनी जड़ों को सुदृढ़ करने की जद्दोजहद करती रही है। भाजपा के प्रयास दक्षिण में बेअसर ही रहे हो, ऐसी बात भी नहीं है, समय-समय पर उसके प्रयास रंग लाते रहे हैं। दक्षिण के चार में से तीन राज्यों में भाजपा अपना प्रभाव और प्रभुत्व दिखा चुकी है। कर्नाटक में कई बार भाजपा सत्ता आसीन हो चुकी है, आंध्र प्रदेश में इस समय सत्ता की भागीदार है, तेलंगाना में भी भाजपा मजबूत पकड़ बना चुकी है, केवल तमिलनाडु ही है जहां भाजपा कई दशकों से उपस्थिति दर्ज कराने के बावजूद सत्ता तक नहीं पहुंच पायी है। मोदी के प्रभाव और भाजपा के विशाल संसाधनों के बावजूद तमिलनाडू जीतना उसके लिए मुश्किल रहा है। पिछले 78 सालों में यहां कभी भी भाजपा-संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा या हिंदुत्व के उनके संस्करण को स्वीकार नहीं किया है। यह सिर्फ भाजपा के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक बड़ी वैचारिक लड़ाई है। लेकिन इस बार भाजपा की रणनीति एवं तैयारियों एवं मोदी-शाह के संकल्पों एवं इरादों में दम है, तमिलनाडु में आमूल-चूल परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। तमिलनाडु में भाजपा की राजनीतिक रणनीति में किये गये बदलाव एवं रणनीतियां एक बड़ा मोड़ है, एक नया उजाला है। राजनीति के चाणक्य अमित शाह का यह भरोसा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा और राज्य में सरकार बनाएगा, कोरी हवा में उछाली गयी बात नहीं है। एआईडीएमके और भाजपा के बीच गठबंधन 1998 से बनते-बिगड़ते रहे हैं। 1998 की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनाने और फिर 13 महीने बाद उसे गिराने का श्रेय भी एआईडीएमके को जाता है। जे. जयललिता का जब तक जीवनकाल रहा तब तक भाजपा नेतृत्व के साथ एआईडीएमके की नजदीकियां बनी रही। जब 1999 में जयललिता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया तो करुणानिधि ने डीएमके को भाजपा के साथ जोड़ लिया और 2004 तक सत्ता का सुख लेते रहे। 2004 के आम चुनाव में फिर से एआईडीएमके भाजपा के साथ आई लेकिन तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें नहीं जीत सकी। लेकिन मोदी-शाह की नजरें हमेशा इस राज्य पर लगी रही।

क्योंकि सामरिक रूप से तमिलनाडु एक संवेदनशील राज्य है, श्रीलंका के साथ उसका सीधा जुड़ाव है। चीन श्रीलंका के माध्यम से भारत में पैठ बनाना चाहता है, ऐसे में तमिलनाडु में केंद्र की आंख बंद कर विरोध करने वाली पार्टी का सत्तासीन रहना देश हित के लिए गंभीर सवाल पैदा करता है, अनेक संकटों का कारण बन सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपने तीसरे कार्यकाल की बड़ी चुनौतियों में बंगाल, तमिलनाडु, केरल को जीतना है। वैसे इन राज्यों में भाजपा की जीत एक करिश्मा ही होगा, लेकिन मोदी-शाह ऐसे आश्चर्यकारी करिश्में घटित करते रहे हैं। सर्वविदित है कि भाजपा के लिए तमिलनाडु केवल राजनीतिक संघर्ष का मैदान नहीं है, वैचारिक लड़ाई भी लड़ी जानी है। स्टालिन सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विवादित करने और त्रिभाषा सिद्धांत को हिंदी थोपने की कोशिश के रूप में प्रचारित करने से केंद्र आहत है, इसीलिये भाजपा अपने राजनीतिक सिद्धांतों, योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों को गंभीर चुनौती दे रहे इन नेताओं और दलों को वैचारिक धरातल पर परास्त करने का रास्ता भी खोज रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्राओं एवं अन्य चचाओं में यह बताते रहे हैं कि पूरे तमिलनाडु की जनता एवं राज्य उनके दिल में हैं, वे उसके कल्याण एवं विकास के लिये तत्पर है। तमिल लोगों के दिलों को जीतने का काम अकेले भाजपा के द्वारा संभव नहीं है, इसीलिये एआईडीएमके की बैशाखियां उसके लिये जरूरी है।

भाजपा के राजनीतिक समीकरणों की सार्थक निष्पत्ति का एक हिस्सा है एआईडीएमके और भाजपा के ताजा गठबंधन की घोषणा। इस गठबंधन को सहज बनाने और पार्टी के अनुरूप इसका स्वरूप देने का श्रेय गृहमंत्री अमित शाह को जाता है, क्योंकि इस बार यह काम उतना आसान नहीं था। शाह एक कद्दावर नेता होने के साथ राजनीतिक गणित को समझने में माहिर है। अमित शाह जमीनी हकीकत से हमेशा वाकिफ रहते हैं। उनके पास तमिलनाडु को लेकर साफ तस्वीरें हैं, सुस्पष्ट एजेंडा है। वह एआईडीएमके के साथ अभी से उदार एवं लचीली सोच से चलना चाहते हैं लेकिन उन्हें अपना लक्ष्य पता है। डीएमके एवं स्टालिन का अहंकार ही उनका मुख्य हथियार होगा। विकास के लिये सत्ता परिवर्तन जनता के लिए यदि जरूरी है तो उसे हासिल करने का तरीका भला अमित शाह से ज्यादा कौन जानता होगा। तमिल में भाजपा के पांव जमते हुए दिख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है भाजपा की सोच में बदलाव आना, तमिलों की बारीकियों एवं भावनाओं को समझते हुए राजनीतिक दांव चलना। भाजपा के पास द्रविड़ समाज को आकार देने का भले ही संस्थागत इतिहास नहीं है, लेकिन राज्य के विकास में उसने गहरे. संसाधन लगाये हैं। वह एक नया वोट-आधार तैयार कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने काशी और तमिलनाडु के बीच विभेद को खत्म करने की कोशिश की। धार्मिक राजत्व का तमिल प्रतीक सेंगोल संसद में स्थापित किया गया। ऐसे अनेक सकारात्मक प्रयास भाजपा के द्वारा लगातार किये जा रहे हैं। त्रिभाषा फामूर्ला भी तमिल लोगों को भाषा के नाम पर जोड़े रखने का एक उपक्रम है। मोदी और शाह दोनों ने तमिल भाषा के प्रति पार्टी के सम्मान को परिभाषित किया। पिछले दशक का एक बड़ा राष्ट्रीय घटनाक्रम यह रहा है कि भाजपा ने चुपचाप अपने नारे हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान में सुधार किया है। अब वे ह्यहिंदी और सभी क्षेत्रीय भाषाओंह्ण की बात करते हैं। इन सबके चलते यदि तमिल के जातीय-मतदाता भाजपा को उसके मौजूदा स्वरूप में स्वीकार करेंगे, तब यह भारतीय सेकुलर राजनीति की एक क्रांतिकारी घटना होगी।

शाह की रणनीति सही दिशा में काम कर रही है। बावजूद यह डगर चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि डीएमके दुबारा सत्ता में आने के लिए जो नुस्खा तैयार कर रही है उसमें तमिल स्वाभिमान और भाषा विवाद का घोल मिलाया जा रहा है। स्टालिन और उनका पूरा परिवार इस समय घोर भ्रष्टाचार और गैर कानूनी कामों में लिप्त है लेकिन उन्होंने हिंदी विरोध, दक्षिण के साथ केन्द्र का कथित सौतेला व्यवहार और मनमाने परिसीमन जैसे मुद्दों को आगामी चुनाव का एजेंडा बनाया है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु यात्रा में जानबूझ कर मुख्यमंत्री स्टालिन गायब हो गए, जबकि यह एक सामान्य शिष्टाचार होता है कि प्रधानमंत्री प्रांत में आये तो मुख्यमंत्री उनका स्वागत करें। लेकिन ऐसा न करके स्टालिन ने यह जताया कि डीएमके भाजपा विरोध के साथ-साथ केंद्र से टकराव की राजनीति पर है।

अपनी बेअदबी आमंत्रित करने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री

- अनिल जैन

मुख्यमंत्री स्टालिन के प्रधानमंत्री की अगवानी नहीं करने और उनके साथ सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने को निश्चित ही उचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो किया उसे भी सही नहीं ठहराया जाएगा। उन्होंने राज्य के लोगों की संवेदनशीलता को नजरअंदाज करते हुए भाषा के सवाल पर स्टालिन का मजाक उड़ाया।

नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके साथ किसी भी विपक्ष शासित राज्य के मुख्यमंत्री के रिश्ते सामान्य नहीं है। प्रधानमंत्री और विपक्षी मुख्यमंत्रियों के बीच टकराव के चलते कई बार दोनों तरफ से सामान्य शिष्टाचार भी नहीं निभाया जाता है। पिछले 10 वर्षों में ऐसे कई मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री की ओर बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक का विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया है। ऐसा भी कई बार हुआ है कि जब प्रधानमंत्री किसी विपक्ष शासित राज्य के दौरे पर गए तो वहां के मुख्यमंत्री ने उनकी अगवानी नहीं की और प्रधानमंत्री के साथ सरकारी कार्यक्रम से भी दूरी बना कर रखी। हाल ही में प्रधानमंत्री की तमिलनाडु यात्रा के दौरान भी ऐसा ही हुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने की 6 तारीख को तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे थे, जहां राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन न तो उनकी अगवानी करने पहुंचे और न ही उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ पम्बन रेलवे ब्रिज के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। इसकी प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाषा के सवाल पर मुख्यमंत्री स्टालिन का अशोभनीय मजाक उड़ाया, जिससे केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति, त्रिभाषा फॉमूर्ला, परिसीमन जैसे मुद्दों पर जारी टकराव नए स्तर पर पहुंच गया।

मुख्यमंत्री स्टालिन के प्रधानमंत्री की अगवानी नहीं करने और उनके साथ सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने को निश्चित ही उचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो किया उसे भी सही नहीं ठहराया जाएगा। उन्होंने राज्य के लोगों की संवेदनशीलता को नजरअंदाज करते हुए भाषा के सवाल पर स्टालिन का मजाक उड़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा और कहा कि उनके पास तमिलनाडु के नेताओं के पत्र आते हैं लेकिन उन पर दस्तखत तमिल में नहीं होते हैं। मोदी ने तंज करते हुए कहा कि 'तमिल गौरव' बना रहे, इसके लिए कम से कम तमिल में दस्तखत करना तो शुरू करें।

सवाल है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बातें करनी शोभा देती हैं? वे खुद भाषाई आधार पर बने एक राज्य से आते हैं लेकिन क्या गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए गुजराती भाषा का गौरव बढ़ाने के लिए उन्होंने कभी गुजराती में दस्तखत किए? प्रधानमंत्री ने स्टालिन को चिढ़ाने के लिए उन्हें मेडिकल की पढ़ाई तमिल में कराने की कटाक्ष भरी नसीहत भी दी। सवाल है कि सारे देश में हिंदी को प्रमुखता दिलाने में लगी मोदी सरकार मेडिकल और इंजीनियरिंग का एक भी बैच हिंदी में पढ़ाकर निकाल सकती है?

बहरहाल, यह पहला मौका नहीं था जब प्रधानमंत्री किसी विपक्ष शासित राज्य के दौरे पर गए और वहां के मुख्यमंत्री ने उनकी अगवानी नहीं की या उनके सरकारी कार्यक्रम से अपने को दूर रखा। हाल के वर्षों में ऐसे कई मौके आए हैं। साल 2022 में तेलंगाना में दो बार ऐसा हुआ जब प्रधानमंत्री के दौरे से तत्कालीन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने अपने को दूर रखा। उसी साल प्रधानमंत्री दो बार महाराष्ट्र के दौरे पर गए लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनकी अगवानी नहीं की।

क्या हम बहुसंख्यक तानाशाही के दौर में प्रवेश कर चुके हैं ?

महज तीन साल पुरानी बात है जब बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय प्रमुख ने अपने अधीन समन्वित ग्रामीण विकास केंद्र में छात्रों को गाय के गोबर के उपले बनाने का प्रशिक्षण देने के लिये कार्यशाला आयोजित की और खुद ही उसका वीडियो वायरल किया। इससे घटना से कुछ ही दिनों पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के सर्वाधिक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक हंसराज कॉलेज में महर्षि दयानन्द सरस्वती के नाम पर गौ संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र खोलने की खबर आई थी और इससे भी कुछ बरस पहले मध्यप्रदेश में एक संघनिष्ठ कुलपति ने शहर के बाहर बनने वाले विश्वविद्यालय के नये परिसर में गौशाला स्थापित करने का निर्णय कर लिया था। उन्होंने महापरिषद और प्रबंध समिति की मंजूरी के बिना गौशाला के संचालन के लिए अखबारों में निविदा विज्ञप्ति तक जारी कर दी थी, ये बात और है कि उस फैसले पर अमल नहीं किया जा सका।

ये बातें याद इसलिये आईं कि सोशल मीडिया पर फिर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक महिला किसी कक्षा की दीवार पर गोबर लीप रही है। बताया गया कि ये मोहतरमा दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्राचार्य प्रत्यूष वत्सला हैं। वे संस्थान परिसर में गाय पालती हैं और अभी हनुमान जयंती पर कॉलेज में सुंदरकांड का पाठ भी उन्होंने करवाया। इतना ही नहीं, नवरात्र के दौरान वे कॉलेज में दुर्गा स्थापना भी करवाती हैं। किसी उच्च शिक्षा संस्थान में धार्मिक कर्मकांड का यह अकेला मामला नहीं है। हाल ही में उत्तर

प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में, नये विभागाध्यक्ष ने पदभार ग्रहण करने से पहले पूजा-पाठ करवाया। दूसरी तरफ तमिलनाडु के राज्यपाल ने संविधान और अपने पद की गरिमा के खिलाफ जाकर मदुरै के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों से जय श्रीराम का नारा लगवा दिया।

इन घटनाओं के बरक्स मेरठ,भागलपुर और शिमला में जो हुआ, उसे देखा जाना चाहिये। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग द्वारा पिछले दिनों ईद मिलन समारोह आयोजित किया जाना था। इसका पता चलते ही एक छात्र नेता ने धमकी दी कि शिक्षा के मंदिर में किसी तरह के भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाना चाहिये और अगर विश्वविद्यालय परिसर में ईद मिलन का कार्यक्रम आयोजित होता है तो फिर वह खुद विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। इस धमकी का नतीजा यह हुआ कि ईद मिलन का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में शिक्षक संघ ने ईद मिलन समारोह का आयोजन किया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आपत्ति जताई और कहा कि नवदुर्गा के समय कॉलेज प्रशासन ने गरबा के लिये जगह नहीं दी थी, इसलिये कॉलेज में ईद मिलन भी नहीं होना चाहिये।

शिमला के एक निजी स्कूल में नर्सरी से दूसरी कक्षा तक के छात्रों के लिए ईद मनाने का कार्यक्रम तय किया था और इसके लिये छात्रों को कुर्ता-पायजामा, टोपी पहनकर आने और टिफिन में सेवइयां लाने को कहा गया था। स्कूल प्रशासन के इस निर्देश पर हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने इसे हिंदू संस्कृति के खिलाफ साजिश बताया और कहा कि यह भारत के संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्कूल ने अपना निर्देश वापस नहीं लिया गया तो स्कूल का घेराव किया जायेगा और कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। मजबूर स्कूल प्रबंधन ने ईद मनाने का कार्यक्रम को रद्द कर दिया। हालांकि उसने साफ किया कि यह आयोजन केवल सांस्कृतिक विविधता को समझाने और छात्रों को विभिन्न त्योहारों से परिचित कराने के उद्देश्य से किया जा रहा था।

क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि किसी शैक्षणिक परिसर में पूजा-पाठ, यज्ञ-हवन होने, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने, दुर्गोत्सव और गणेशोत्सव मनाने जैसे क्रियाकलाप हों तब किसी को याद नहीं आता कि कोई एक नहीं, बल्कि सारे ही शिक्षा संस्थान, शिक्षा के मंदिर हैं। संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा छात्रों से जय श्रीराम के नारे लगवाने पर किसी को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का ख्याल नहीं आता। लेकिन अगर कोई आयोजन दूसरे धर्म से जुड़ा हो।

यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस और स्वीडन में तनातनी

एजेंसी

स्टाकहोम । रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोपीय देशों ने रूस पर दवाब बनाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरूआत स्वीडन ने कर दी है। हाल ही में यूक्रेन मिसाइल हमले करने पर स्वीडन ने रूस के राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया है। स्वीडिश विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक इंटरनेशनल मानवीय नियमों के मुताबिक लोगों के बुनियादी ढांचों की सुरक्षा करना रूस का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। इस मामले में स्वीडन ने रूस के राजदूत से अपने देश का रूख भी स्पष्ट करने को कहा है। इस तरह राजदूत को तलब करना यह दिखाता है कि स्वीडन यूक्रेन पर हमलों को लेकर रूस के प्रति खासा नाराज है। गौरतलब है कि रविवार को रूस ने यूक्रेन के सुमी शहर पर मिसाइल से हमला किया था। इस हमले में 35 लोग मारे गए थे।

नेपाली कांग्रेस के महामंत्री का आरोप, कहा- बिचौलियों की पहुंच पीएम ओली के बेडरूम तक

काठमांडू। नेपाल की दो तिहाई की गठबंधन सरकार के भीतर एक बार फिर से विवाद अपने चरम पर पहुंच गया है। सत्तारूढ़ गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल नेपाली कांग्रेस के महामंत्री ने आरोप लगाया है कि यह सरकार बिचौलियों से घिरी है, जिनकी पहुंच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बेडरूम तक है। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा ने राजधानी काठमांडू में मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा कि ओली सरकार अभी भी ट्रैक्टर के स्पीड से चल रही है।उन्होंने कहा कि देश बिचौलियों के हाथ में है, जिनकी पहुंच पीएम के बेडरूम तक है। ओली सरकार को असफल बताते हुए गागा थापा ने कहा कि जिस उद्देश्य से इस सरकार का गठन किया गया था, वह उद्देश्य से भटक गया है। नेपाल के केंद्रीय बैंक के गवर्नर की नियुक्ति का प्रसंग उठते हुए कांग्रेस के महामंत्री थापा ने कहा कि सरकार में अच्छे और सच्चे तथा ईमानदार व्यक्ति को गवर्नर बनाने को लेकर चर्चा होने के बजाए किस बिचौलिए का कौन उम्मीदवार है और उनमें से किसकी नियुक्ति होगी, इस बात पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में की गई सभी नियुक्तियों में कोई न कोई बिचौलिया ही हावी रहा है। देश की खराब होती अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए गगन थापा ने कहा कि इसके लिए भी कुछ बड़े बिचौलियों की शीर्ष स्तर के नेताओं तक पहुंच ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि इस देश के बिचौलिए इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि बजट की नीति में क्या संशोधन करना है, टैक्स स्लैब क्या रखना है, किन वस्तुओं पर कर बढ़ाना है, किस पर घटाना है, किन वस्तुओं के आयात कर को बढ़ाना है, किसको घटाना है, ये सभी सरकार के बड़े बिचौलिया ही तय करते हैं।

ईरान-अमेरिका परमाणु वार्ता पर खामेनेई का सधा हुआ बयान, न ज्यादा उम्मीद, न निराशा

तेहरान। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका के साथ चल रही परमाणु वार्ता को लेकर तटस्थ रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि वह इस प्रक्रिया को लेकर न तो अत्यधिक आशावादी हैं और न ही निराशावादी। खामेनेई का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब हालिया वार्ताओं के बाद देश में संभावित आर्थिक सुधार की उम्मीदें तेज हो गई हैं। गत सप्ताहांत ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत को दोनों देशों ने सकारात्मक बताया था। इसके बाद ईरानी मुद्रा रियाल में लगभग 20 प्रतिशत की मजबूती देखी गई, जिससे आम लोगों को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत की आशा जगी है। खामेनेई ने संसद सदस्यों के साथ बैठक में कहा, ÷यह एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत ठीक दिशा में हुई है। लेकिन इसे सतर्कता से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों के लिए लाल रेखाएं तय की जानी चाहिए ताकि आगे कोई अस्पष्टता न रहे। हालांकि उन्होंने जनता को यह चेतावनी भी दी कि इन वार्ताओं को लेकर अत्यधिक उम्मीदें न पालें और देश की दिशा को इन पर निर्भर न करें। ईरान के शीर्ष नेता का यह बयान संकेत देता है कि तेहरान अब भी अमेरिकी नीतियों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, खासकर 2018 की उस घटना के बाद जब तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में हुए परमाणु समझौते को रद्द कर दिया था और ईरान पर फिर से सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे।

पेरू के पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के मामले में 15 साल की सजा

लीमा। पेरू की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला और उनकी पत्नी नादिन हेरेडिया को धन शोधन का दोषी पाते हुए 15 साल जेल की सजा सुनाई है। जज नायको कोरोनाडो की अध्यक्षता वाली थर्ड नेशनल कोलीजिएट क्रिमिनल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अन्य न्यायाधीशों ने फैसले का समर्थन किया। अदालत ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने लगभग नौ महीने पूर्व-ट्रायल हिरासत (ट्रायल से पहले की गिरफ्तारी) में बिताए हैं, उन्हें सजा की अवधि में शामिल माना जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पर आरोप है कि ब्राज़ील की निर्माण कंपनी ओडेब्रेच ने 2006 से 2011 के बीच नेशनलिस्ट पार्टी को चुनावी अभियान के लिए उन्हें अवैध रूप से धन मुहैया कराया था।

चीन में 'भारतीय दोस्तों' का स्वागत : अमेरिका के साथ टैरिफ युद्ध में उलझे बीजिंग ने जारी किए 85,000 वीजा

एजेंसी

बीजिंग । भारत स्थित चीनी दूतावास ने 1 जनवरी से 9 अप्रैल, 2025 के बीच भारतीय नागरिकों को 85,000 वीजा जारी किए। दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के एक बड़े प्रयास के तहत यह कदम उठाया गया। चीनी राजदूत जू फेइहोंग ने एक्स पर लिखा, '9 अप्रैल, 2025 तक, भारत में चीनी दूतावास और वाणिज्य दूतावासों ने इस वर्ष चीन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को 85,000 से अधिक वीजा जारी किए हैं। चीन आने के लिए अधिक से अधिक भारतीय मित्रों का स्वागत है, ताकि वे एक खुले, सुरक्षित, जीवंत, ईमानदार और मैत्रीपूर्ण चीन का अनुभव कर सकें। वीजा की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, 2025 के पहले चार महीनों में ही 85,000 वीजा जारी किए गए हैं। जबकि 2023 तक 1,80,000 वीजा जारी किए गए थे। पिछले वर्ष, चीनी दूतावास ने अपने वीजा आवेदन शर्तों को अपडेट किया

था और कई प्रमुख छूटें प्रदान की थीं। भारतीय आवेदकों को अब अपने वीजा आवेदन जमा करने से पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वे सीधे कार्य दिवसों के दौरान वीजा केंद्रों पर आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं 180 दिनों से कम अवधि के लिए अल्पकालिक, एकल या दोहरे प्रवेश वाले वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों को फिंगरप्रिंट जैसे बायोमेट्रिक डाटा प्रदान करने से छूट दी गई। इन परिवर्तनों के साथ-साथ, चीनी दूतावास ने वीजा आवेदन शुल्क भी कम कर दिया है। आवेदकों के लिए नए, कम शुल्क लागू किए हैं। चीन ने यह जानकारी ऐसे समय में जारी कि है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग हर देश पर संभावित व्यापार शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। उनके निशाने पर विशेष तौर पर चीन है, जो वाशिंगटन का प्रमुख व्यापारिक साझेदार और आर्थिक प्रतिद्वंद्वी है। ट्रंप ने चीनी आयात पर अमेरिकी टैरिफ को बढ़ाकर 145 प्रतिशत कर दिया है, जबकि अन्य देशों के सामानों पर नए टैरिफ को रोक दिया है। जवाबी कार्रवाई में, चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 125 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। चीन ने भारत और अन्य देशों से भी अपील की कि वे अमेरिकी टैरिफ दुरुपयोग के खिलाफ खड़े हों। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने पिछले सप्ताह कहा था कि भारत और चीन, दो सबसे बड़े विकासशील देशों के रूप में, अमेरिकी टैरिफ कार्रवाइयों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए।

ट्रम्प की चेतावनी, राजनीतिक रुख के कारण हार्वर्ड का टैक्स छूट का दर्जा हो सकता है रद्द

एजेंसी

वॉशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय की टैक्स छूट को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय राजनीतिक, विचारधारात्मक और आतंक-समर्थक मानसिकता को बढ़ावा देता रहा, तो उसकी टैक्स छूट रद्द कर दी जा सकती है और उसे एक राजनीतिक इकाई के रूप में कर देना पड़ सकता है। ट्रंप ने यह टिप्पणी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए की। उन्होंने लिखा, अगर हार्वर्ड राजनीतिक, वैचारिक और आतंक-प्रेरित/समर्थक बीमारी को बढ़ावा देता रहा, तो शायद उसे टैक्स छूट की स्थिति से वंचित कर दिया जाना चाहिए और एक राजनीतिक इकाई की तरह टैक्स लगाया जाना चाहिए। ट्रंप का यह बयान उस पृष्ठभूमि में आया है जब हार्वर्ड ने उनके प्रशासन की कुछ मांगों को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि विश्वविद्यालय ने इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यह मुद्दा अमेरिका में शिक्षा संस्थानों की स्वतंत्रता और उनकी राजनीतिक भूमिकाओं को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में विश्वविद्यालयों को टैक्स छूट का दर्जा शिक्षा और शोध के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण दिया जाता है, न कि उनके राजनीतिक विचारों के आधार पर। लेकिन ट्रंप के इस बयान ने इस बहस को फिर से जीवंत कर दिया है कि क्या शिक्षण संस्थानों को अपनी वैचारिक स्थिति के कारण दंडित किया जा सकता है।

अमेरिका के टेक्सास में खसरे का प्रकोप, 560 से अधिक मामले सामने आए

एजेंसी

ह्यूस्टन । अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े राज्य टेक्सास में खसरे के 561 मामले सामने आए। टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हेल्थ सर्विसेज (डीएसएचएस) ने यह जानकारी दी। डीएसएचएस ने बताया कि पिछले पांच दिनों में 20 नए केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही अब तक खसरे से पीड़ित 58 रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएसएचएस ने संभावना जताई कि रोग के अत्यधिक संक्रामक होने के कारण इसके मामलों में वृद्धि हो सकती है। अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने शुक्रवार को बताया कि इस साल करीब 24 राज्यों में खसरे के 712 मामले सामने आए। इनमें से लगभग 97 प्रतिशत मामले उनके हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है या जिनके वैक्सीनेशन की स्थिति स्पष्ट नहीं है।समाचार एजेंसी की मानें तो टेक्सास के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने पिछले महीने ही चेतावनी दी थी कि यह प्रकोप कई महीनों तक या पूरे साल तक जारी रह सकता है। उन्होंने बताया कि औसत से कम टीकाकरण स्तर वाली समुदायों को इस प्रकोप से सबसे

अधिक नुकसान हो रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रकोप जारी रहा तो संयुक्त राज्य अमेरिका 2000 में घोषित खसरे से मुक्त होने का दर्जा खो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है। संक्रमित व्यक्ति के सांस लेने, खांसने या छींकने के कारण यह आसानी से फैलता है। यह गंभीर बीमारी मौत का कारण भी बन सकता है। कोई भी शख्स इस बीमारी के चपेट में आ सकता है लेकिन यह बच्चों में सबसे आम है। यह बीमारी सांस लेने वाले तंत्र को संक्रमित करती है और फिर पूरे शरीर में फैल जाती है। खसरा के लक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें तेज बुखार, खांसी, नाक बहना और पूरे शरीर पर दाना आना शामिल है। खसरे से बीमार होने या दूसरे लोगों में फैलने से रोकने के लिए टीका लगवाना ही सबसे बेहतर विकल्प है। 1963 में खसरे के टीके की शुरुआत और व्यापक टीकाकरण से पहले, बड़ी महामारियां लगभग हर दो से तीन साल में होती थीं और हर साल अनुमानतः 2.6 मिलियन लोगों की मृत्यु होती थी। टीके की दो खुराकें लेने की सिफारिश की जाती हैं ताकि प्रतिरक्षा सुनिश्चित हो और प्रकोप को रोका जा सके, क्योंकि पहली खुराक से सभी बच्चों में प्रतिरक्षा विकसित नहीं होती।

लीबिया में नाव पलटी, 4 पाकिस्तानी नागरिकों समेत 11 लोगों की मौत

एजेंसी

इस्लामाबाद । उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया में नाव पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 पाकिस्तानी नागरिक थे। यह जानकारी पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने दी। यह नाव पूर्वी लीबिया के सिर्ते के निकट हरावा तटरेखा के पास विदेशी प्रवासियों को ले जा रही थी। मारे गए चारों पाकिस्तानी सहित सभी 11 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस दुर्घटना पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुख व्यक्त किया।

उन्होंने देश के नागरिकों को ऐसे मौत के जाल में फंसाने के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीरिया की राजधानी त्रिपोली में पाकिस्तानी मिशन और विदेश कार्यालय को स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क कर बचे हुए मृतकों को निकालने के आदेश दिए हैं।जारी एक बयान में प्रधानमंत्री ने कहा, लीबिया में पाकिस्तानी मिशन से सिर्ते शहर के

नजदीक हरावा तटरेखा के पास एक और नाव पलटने की घटना की जानकारी मिलने से दुखी हूं। हमारा मिशन और विदेश कार्यालय स्थानीय अधिकारियों के साथ बचे हुए लोगों के शवों को निकालने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। शरीफ ने आगे कहा कि हमारे नागरिकों को इस मौत के जाल में फंसाने वालों के खिलाफ हम ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखेंगे ताकि किसी भी परिवार को ऐसी घटनाओं में अपने प्रियजनों के ताबूत को ले जाने की जरूरत न पड़े। पाकिस्तानी दूतावास की टीम ने सिर्ते शहर पहुंचने के बाद पाकिस्तानी नागरिकों की मौत की पुष्टि की।

अफगानिस्तानः भूकंप के झटकों से हिला हिंदुकुश क्षेत्र, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.9 मापी गई

एजेंसी

काबुल। अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई है। एनसीएस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ÷बुधवार तड़के स्थानीय समयानुसार 4ः43 बजे अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई है। भूकंप का केंद्र 35.83 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70.60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 75 किलोमीटर की गहराई पर था। अभी तक किसी के हताहत होने या इमारतों को नुकसान की कोई तत्काल खबर नहीं है, लेकिन अधिकारी और मानवीय एजेंसियां स्थिति पर करीब से नजर रख रही हैं। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला (जो उत्तर-पूर्वी

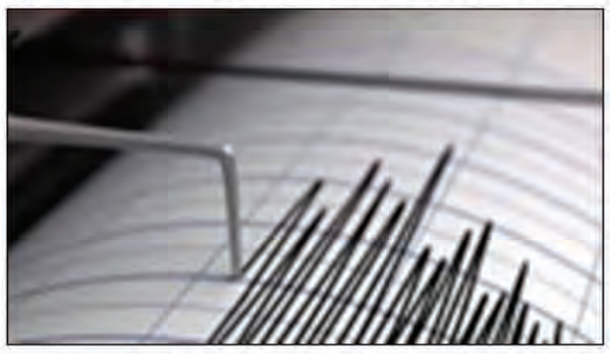

अफगानिस्तान में फैली है) यह अत्यधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र का हिस्सा है, जहां जटिल टेक्टोनिक संरचना के कारण भूकंप बार-बार आते हैं। अफगानिस्तान भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव वाले क्षेत्र में स्थित है, जो इसे विशेष रूप से भूकंपीय गतिविधि के लिए संवेदनशील बनाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (यूएनओसीएचए) ने देश की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता को दोहराया, और कहा कि बार-बार आने वाले भूकंप उन समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, जो पहले से ही दशकों के संघर्ष और पुराने अविकास से कमजोर हो चुके हैं। रेड क्रॉस के अनुसार, अफगानिस्तान में विशेष रूप से हिंदुकुश जैसे भूगर्भीय रूप से अस्थिर क्षेत्रों में हर साल शक्तिशाली भूकंप आते हैं। पश्चिमी प्रांत हेरात भी एक महत्वपूर्ण फॉल्ट लाइन पर स्थित है, जो देश के भूकंपीय जोखिम को और बढ़ाता है। अक्टूबर 2023 में, 6.3 तीव्रता सहित कई शक्तिशाली भूकंपों ने पश्चिमी अफगानिस्तान, विशेष रूप से हेरात को तबाह कर दिया था, जिसमें 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग विस्थापित हुए थे।

अमेरिकी नागरिकता के लिए इंटरव्यू देने गया फिलिस्तीनी छात्र गिरफ्तार

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे फिलिस्तीनी छात्र को मंहगा पड़ गया। उसे अमेरिका की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छात्र पर आरोप है कि गाजा युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में छात्र ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। फिलीस्तीनी छात्र मोहसिन महदावी पिछले करीब दस साल से अमेरिका में रह रहा

है। वह 2015 से वहां का ग्रीन कार्ड धारक भी है। वह अमेरिकी नागरिकता के लिए यूएस स्टेट वर्मोट के इमिग्रेशन दफ्तर में पहुंचा था। जब वह नागिरकता के लिए इंटरव्यू देने अंदर आफिस में गया तो उसे पहले हिरासत में लिया गया। उसके बाद लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। छात्र अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुका है। अब वह मास्टर डिग्री करना चाहता है।उधर गिरफ्तार किए गए छात्र महदावी के वकील लूना ड्रोबी ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ने छात्र को फिलिस्तीनियों के समर्थन में आवाज उठाने के कारण गिरफ्तार किया है। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है।

विकासशील देशों पर नए अमेरिकी 'टैरिफ़' मत थोपिएः यूएन व्यापार प्रमुख

एजेंसी

वाशिंगटन। आयात शुल्क (टैरिफ़) थोपे जाने की ख़बरों से विश्व बाज़ारों व व्यापार जगत में बड़ी उथल-पुथल मची है और आशंकाएँ व अनिश्चितताएँ गहरा रही हैं. इस पृष्ठभूमि में, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास एजेंसी की प्रमुख रेबेका ग्रीनस्पैन ने यूएन न्यूज़ के साथ एक बातचीत में बताया कि उन निर्धनतम देशों को इन शुल्कों से छूट दी जानी चाहिए, जिनकी गतिविधियों का व्यापार घाटे पर मामूली असर ही है. संयुक्त राष्ट्र ने चिन्ता जताई है कि व्यापार क्षेत्र में पसरी अनिश्चितता का उन अर्थव्यवस्थाओं पर असर हो सकता है जोकि पहले से ही सम्वेदनशील हालात का सामना कर रही हैं.इससे पहले, यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने मंगलवार को कहा था कि व्यापार युद्ध बेहद नकारात्मक हैं, और उनके भयावह नतीजे सामने आ सकते हैं. टैरिफ़ किसी देश में आने वाले आयात पर लगाया जाने वाला कर है, जिसका भुगतान आमतौर पर निर्यातक को करना होता है. यह सामान के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लिया जाता है. यानि, एक अतिरिक्त क़ीमत, जिससे सामान महंगा होता है और इसे फिर आमतौर पर उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है. की शीर्ष अधिकारी ने गुरूवार को फ़ाइनेंशियल टाइम्स में प्रकाशित एक साक्षात्कार में, अमेरिका से अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने की अपील की. उन्होंने कहा कि ऐसे 44 सबसे कम विकसित देश हैं, जिनका योगदान अमेरिका के व्यापार घाटे में दो प्रतिशत से भी कम है. अधिक टैरिफ़ थोपे जाने से उनका मौजूदा ऋण संकट और भी बदतर हो जाएगा. रेबेका ग्रीनस्पैन ने यूएन न्यूज़ को बताया कि हृष्टञ्जष्ठ द्वारा विकासशील देशों को कई प्रकार से सहयोग मुहैया कराया जा रहा है. साथ ही, उन्होंने क्षेत्रीय व्यापार सम्बन्धों को और भी मज़बूत बनाए जाने की वकालत की, जिससे इन देशों को अन्तरराष्ट्रीय व्यापार वार्ता में अपना पक्ष मज़बूती से सामने रखने में मदद मिलेगी.इस इंटरव्यू को संक्षिप्तता व स्पष्टता के लिए सम्पादित किया गया है.यूएन न्यूज़ः दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, एक दूसरे पर भारी व्यापार शुल्क थोपने या उसकी धमकी देने की प्रक्रिया में हैं. आपके अनुसार, ये हमारे लिए कितनी बड़ी चिन्ता का विषय हैरेबेका ग्रीनस्पैनः जब दो मुख्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाएँ शुल्क लगाती हैं, तो इसका असर सिर्फ़ टैरिफ़ युद्ध में शामिल अर्थव्यवस्थाओं पर ही नहीं, बल्कि हर किसी पर पड़ता है. हम पहले से ही कम विकास और ऊँचे कर्ज़ के 'नए सामान्य' हालात का सामना कर रहे हैं, और हम चिन्तित हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो जाएगी. हमारा ध्यान सम्वेदनशील हालात से जूझ रहे देशों पर इससे होने वाले प्रभावों पर है, जिनमें सबसे कम विकसित देश और लघु द्वीपीय विकासशील देश शामिल हैं. उन देशों के साथ जो हो रहा है, वह वास्तव में हमें चिन्तित करता है. उ ADB/Deng Jia चीन के आंतरिक मंगोलिया में एक कारखाना (फ़ाइल) यूएन न्यूज़ः कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह युद्ध के बाद बनाई गई अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था का अन्त हो सकता है।

शिक्षकों ने नेपाल सरकार का आग्रह ठुकराया, आंदोलन 15वें दिन भी जारी

एजेंसी

काठमांडः। नेपाल के सभी निजी तथा सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की हड़ताल का 15वां दिन है। देशभर के शिक्षक आज भी काठमांडू की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने शिक्षकों की मांग को देखते हुए संसद का बजट अधिवेशन बुलाने का फैसला भी ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षक महासंघ सिर्फ आश्वासन पर अपनी हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं है। महासंघ ने देशभर के बाकी शिक्षकों को भी काठमांडू आने की अपील की है। प्रधानमंत्री निवास में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के मुद्दों को हल करने के लिए 25 अप्रैल से संसद सत्र बुलाकर शिक्षक संबंधी विधेयक पेश करने का फैसला लिया है। इसके बाद शिक्षा मंत्री विद्या भट्टराई ने हड़ताली शिक्षकों से आंदोलन खत्म करने का आग्रह भी किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि

शिक्षकों की हड़ताल के कारण दसवीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच नहीं हो पा रही है, जिसके साथ ही 12वीं की बोर्ड परीक्षा में भी विलंब हो रहा है। उन्होंने शिक्षा अधिनियम सहित शिक्षकों की मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया है। नेपाल शिक्षक महासंघ की उपाध्यक्ष और सरकार से वार्ता करने के लिए गठित समिति की संयोजक नानुमया पराजुली सहित महासंघ के अन्य नेताओं ने सरकार के इरादे पर अविश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से मौखिक आश्वासन मिला है। संसद सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक विधेयक संसदीय समिति के ही पहुंच पाया है, जहां एक-एक बिंदुओं पर सहमति होने में कम से कम एक महीने का समय लग सकता है। पराजुली ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिन से आंदोलित शिक्षक खाली हाथ वापस नहीं जाने वाले हैं।

मालदीव ने लगाया इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध

एजेंसी

कोलंबो। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव आव्रजन अधिनियम में तीसरे संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इजरायली पासपोर्ट धारकों को मालदीव गणराज्य के क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। राष्ट्रपति

कार्यालय ने यह जानकारी दी। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा कि 15 अप्रैल को वर्ष के पहले सत्र की 20वीं बैठक के दौरान पीपुल्स मजलिस द्वारा संशोधन पारित किया गया। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार मालदीव सरकार फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ अपनी मजबूत एकजुटता और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि मालदीव अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए जवाबदेही की वकालत करना जारी रखेगा और इजरायल की कार्रवाइयों की निंदा करने में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुखर बना हुआ है। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रपति मुइज्जू ने लगातार एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए मालदीव के सैद्धांतिक समर्थन को दोहराया है।

ओडेसा में नाटो महासचिव ने दोहराया समर्थन, यूक्रेन को 22 अरब डॉलर की सुरक्षा सहायता का वादा

एजेंसी

ओडेसा (यूक्रेन)। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा का दौरा करते हुए यूक्रेन के प्रति गठबंधन के अटूट समर्थन को दोहराया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 की पहली तिमाही में नोटो सहयोगी देशों ने यूक्रेन को 20 अरब यूरो (लगभग 22 अरब डॉलर) की सुरक्षा सहायता देने का संकल्प लिया है। रूटे ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, ÷मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि यूक्रेन के नागरिकों को अपने देश में वास्तविक शांति और सुरक्षा का अधिकार है। ओडेसा के एक अस्पताल में उन्होंने जेलेंस्की के साथ घायल सैनिकों से भी मुलाकात की।यह दौरा ऐसे समय हुआ जब हाल ही में रूस ने उत्तर-पूर्वी शहर सुमी पर दो बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें

35 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिनमें दो बच्चे भी शामिल थे, और 119 लोग घायल हुए थे। इससे पहले, 04 अप्रैल को जेलेंस्की के गृहनगर क्रिवी रिह पर भी मिसाइल हमला हुआ था, जिसमें 20 लोगों की जान गई थी। रूटे ने हालिया हमलों को भीषण हिंसा करार देते हुए कहा, इन हालात में बातचीत आसान नहीं है, लेकिन हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू की गई शांति वार्ताओं का समर्थन करते हैं। बता दें कि ट्रंप के नेतृत्व में सऊदी अरब में कीव और मॉस्को के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि, रूस ने युद्धविराम के लिए कई शर्तें लगाकर इस प्रक्रिया को रोक रखा है। इसके बीच, यूरोपीय देशों और यूक्रेन ने मिलकर एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है, जिसे कोएलिशन ऑफ द विलिंग कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य युद्धविराम के बाद भविष्य में किसी भी रूसी आक्रामकता को रोकना है। जेलेंस्की ने बताया कि तुर्की ब्लैक-सी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। तुर्की में चल रही बैठक में यूक्रेन, फ्रांस, ब्रिटेन और तुर्की के सैन्य प्रतिनिधि इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। नाटो प्रमुख ने कहा, ÷यह वार्ता इस बात का संकेत है कि हम भविष्य की सुरक्षा तैयारियों की दिशा में गंभीर हैं।

सीनियर नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप में मध्य प्रदेश की टीम पहली बार बनी उपविजेता

एजेंसी

भोपाल। उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित 15वीं हॉकी इण्डिया सीनियर मेन नेशनल चैम्पियनशिप 2025 डिवीजन-ए का फाइनल मुकाबला मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी और पंजाब की टीम के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब ने मध्य प्रदेश हॉकी टीम को 1-4 से हराकर चैम्पिनयशिप का खिताब अपने नाम किया। इस सीनियर मेन नेशनल चैम्पियनशिप मध्य प्रदेश की टीम पहली बार उपविजेता बनी। प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मध्य प्रदेश हॉकी टीम के खिलाड़ियों के खेल की सराहना करते उपविजेता बनने पर बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि मप्र की टीम पहली बार सीनियर नेशनल के फाइनल मुकाबले में पहुंची थी। खेले गए इस मुकाबले में मध्य प्रदेश की तरफ से 28वें मिनिट में पेनाल्टी कार्नर से प्रताप लाकरा ने एकमात्र किया, जबकि पंजाब की टीम की ओर से 30वें मिनिट में जुगराज सिंह ने पेनाल्टी कार्नर से पहला, 38वें मिनिट में जसकरण सिंह ने फील्ड से दूसरा, 46वें मिनिट में गुरिंदर सिंह ने फील्ड से तीसरा और 49वें मिनिट में जुगराज सिंह ने पेनाल्टी कार्नर से चौथा गोल किया। खेल संचालक राकेश गुप्ता ने मप्र हॉकी टीम के खिलाड़ियों की सराहना करते हुये बताया मध्य प्रदेश की युवा टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। सीनियर नेशनल का यह अनुभव भविष्य में खिलाड़ियों के बहुत काम आयेगा। उन्होनें उप विजेता बनने पर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है।

ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग का उद्घाटन 18 को, हरियाणा के सीएम को विशेष आमंत्रण

गुरुग्राम। ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग (जीआई-पीकेएल) का उद्घाटन समारोह 18 अप्रैल को गुरुग्राम विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी खेल संघ (एचआईपीएसए) की अध्यक्ष कांति डी. सुरेश ने उन्हें एक औपचारिक पत्र के माध्यम से इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने का आग्रह किया है।यह भव्य लीग 13 दिनों तक चलेगी और 30 अप्रैल को पुरुष और महिला दोनों वर्गों के ग्रैंड फाइनल के साथ संपन्न होगी। टूर्नामेंट की शुरुआत पुरुषों के मुकाबलों से होगी, जो प्रत्येक दिन शाम छह बजे से खेले जाएंगे, जिसका सोनी स्पोर्ट्स 3, डीडी स्पोर्ट्स और फैनकोट पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। सुश्री सुरेश ने अपने पत्र में लिखा, ÷कबड्डी को ओलंपिक खेल के रूप में शामिल कराने के भारत सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए हमने अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान और अब विश्व की सबसे बड़ी कबड्डी लीग की शुरुआत की है। इस लीग में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 10 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग शामिल हैं।उद्घाटन के साथ-साथ जीआई-पीकेएल ने भारत के प्रमुख शहरों दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद और मुंबई में आकर्षक आउटडोर प्रचार अभियान चलाया है। 30 से अधिक प्रमुख बिलबोर्ड इस लीग को लोकप्रियता दिला रहे हैं। लीग उद्घाटन के दिन न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर पर एक दिवसीय डिजिटल अभियान भी चलाएगी।

सुदीरमन कप 2025: बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप से बाहर रहने के बाद सात्विक-चिराग की वापसी

नई दिल्ली। सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी फिर से मैदान में उतरने को तैयार है, क्योंकि भारत ने सुदीरमन कप के लिए अपनी 14 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। सुदीरमन कप, 16 देशों की मिश्रित टीम स्पर्धा है जो 27 अप्रैल से 4 मई तक चीन के जियामेन में आयोजित की जाएगी। सात्विक-चिराग ने चोट के कारण पिछले सप्ताह चीन के निंगबो में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि, चोटिल महिला युगल जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद, जो कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में भी नहीं खेल पाई थीं, को टीम में शामिल नहीं किया गया है। भारत ने अपनी विश्व रैंकिंग के आधार पर टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया।

बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग: ट्रीसा-गायत्री की जोड़ी टॉप 10 में बरकरार, सिंधु और लक्ष्य नीचे खिसके

नई दिल्ली। नवीनतम बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला युगल जोड़ी ने शीर्ष 10 में अपना स्थान बरकरार रखा है, जबकि पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जैसे एकल सितारे और नीचे खिसक गए हैं। पिछले सप्ताह चीन के निंगबो में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भाग नहीं लेने वाली ट्रीसा और गायत्री एक स्थान नीचे खिसककर 10वें स्थान पर आ गईं। ओलंपियन तनीषा क्रैस्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी 22वें स्थान पर बनी हुई है। महिला एकल में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु चीन में राउंड-ऑफ-16 से बाहर होने के बाद 17वें से 18वें स्थान पर आ गईं।

आईएसएसएफ विश्व कप: सुरुचि इंदर सिंह ने स्वर्ण, मनु भाकर ने रजत पर किया कब्ज़ा

एजेंसी

नई दिल्ली। । पेरू के लीमा में चल रहे अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आईएसएसएफ) विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सुरुचि इंदर सिंह ने स्वर्ण और मनु भाकर ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं, पुरुष वर्ग में सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक जीतकर लंबे समय बाद वापसी की।

18 वर्षीय सुरुचि ने मनु को 1.3 अंकों से हराया

सुरुचि इंदर सिंह ने चयन दौर (क्वालिफिकेशन राउंड) में 582 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि मनु भाकर ने 578 अंकों के साथ अंतिम आठ (फाइनल-8) में जगह बनाई।फाइनल मुकाबले में सुरुचि ने बेहतरीन निशानेबाजी करते हुए 243.6 अंक अर्जित किए और

अपनी अनुभवी साथी निशानेबाज मनु भाकर (242.3) को 1.3 अंकों से पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। सौरभ चौधरी ने 2022 के बाद जीता पहला व्यक्तिगत पदक

पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सौरभ चौधरी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने चयन दौर में 578 अंक बनाकर सातवें स्थान के साथ अंतिम आठ में जगह बनाई। फाइनल में सौरभ ने जोरदार शुरुआत की और शुरुआती दौर के बाद दूसरे स्थान पर थे। हालांकि, चीन के हु काई ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 246.4 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। ब्राजील के फेलिप अल्मेडा वू ने 241.0 अंक बनाकर रजत पदक हासिल किया। सौरभ ने 219.1 अंक बनाकर कांस्य पदक प्राप्त किया।

वरुण तोमर और अन्य भारतीय निशानेबाजों का प्रदर्शन

अंतिम आठ में पहुंचे एक अन्य भारतीय वरुण तोमर ने 198.1 अंकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया। चयन दौर में आकाश भारद्वाज ने तीसरे सर्वश्रेष्ठ 583 अंक बनाए, लेकिन वह रैंकिंग अंक हेतु (आरपीओ) के अंतर्गत खेल रहे थे, इसलिए पदक स्पर्धा में भाग नहीं ले सके। रविंदर सिंह (574) और अमित शर्मा (आरपीओ, 573) ने क्रमशः 12वें और 16वें स्थान पर स्थान प्राप्त किया।

नेशनल हॉकी चैंपियनशिप :हॉकी पंजाब बना चैंपियन, उत्तर प्रदेश ने कांस्य पदक जीता

एजेंसी

झांसी। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का फाइनल मुकाबला हॉकी पंजाब और हॉकी मध्यप्रदेश के बीच खेला गया, जिसमें हॉकी पंजाब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4-1 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। फाइनल में पंजाब की ओर से जुगराज सिंह ने दो गोल (30वें और 49वें मिनट) कर टीम को मजबूत बढ़त दिलाई। जस्करण सिंह (38) और मनिंदर सिंह (46फीसदी) ने भी एक-एक गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित की। दूसरी ओर, मध्यप्रदेश के लिए एकमात्र गोल प्रताप लकड़ा ने 28वें मिनट में किया। हार के बावजूद हॉकी मध्यप्रदेश ने रजत पदक के साथ टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। जीत के बाद हॉकी पंजाब के कप्तान हार्दिक सिंह ने कहा,हमारा प्लान शुरुआत से आक्रामक खेलने का था और टीम ने इसे बखूबी अंजाम दिया। जुगराज ने बेहतरीन खेल दिखाया। कुछ मौके जरूर चूके लेकिन स्वर्ण पदक जीतकर बेहद खुशी हो रही है।

घरेलू स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करना हमेशा खास होता है। तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में उत्तर प्रदेश हॉकी ने मणिपुर हॉकी को 5-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उत्तर प्रदेश के लिए कुशवाहा सौरभ आनंद ने दो गोल (29फीसदी, 49फीसदी) कर मैच में अहम भूमिका निभाई। शारदानंद तिवारी (35फीसदी), दीप अतुल (48फीसदी) और शिवम आनंद (60फीसदी) ने भी एक-एक गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित की। मणिपुर की ओर से मोइरांगथेम रबीचंद्रन सिंह (45फीसदी) ने एकमात्र सांत्वना गोल किया।

एफा चैंपियंस लीग 2024-25 : गुइरासी की हैट्रिक रही बेकार, बार्सिलोना से हारकर डॉर्टमंड टूर्नामेंट से बाहर

एजेंसी

डॉर्टमंड। यूएफा चैंपियंस लीग 2024-25 के क्वार्टर फाइनल मुक़ाबले में सहरो गुइरासी ने शानदार हैट्रिक लगाई, लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम बोरुसिया डॉर्टमंड प्रतियोगिता से बाहर हो गई। डॉर्टमंड ने दूसरे चरण में बार्सिलोना को 3-1 से हराया, लेकिन पहले चरण में 4-0 की करारी हार के कारण कुल 5-3 के अंतर से पराजित होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वहीं, बार्सिलोना ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है।

पहले चरण की बड़ी हार के बाद डॉर्टमंड ने किया जोरदार हमला

पहले चरण में 4-0 की हार झेलने के बाद डॉर्टमंड के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और बार्सिलोना को बैकफुट पर धकेल दिया। गुइरासी ने पहले चरण में कई अवसर गंवाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने 11वें मिनट में पेनल्टी पर कोई गलती नहीं की और अपनी टीम को बढ़त दिलाई।

गुइरासी की हैट्रिक, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया

दूसरे हाफ में गुइरासी ने 49वें मिनट में हेड से दूसरा गोल किया। इसके बाद 76वें मिनट में नज़दीक से तीसरा गोल कर हैट्रिक पूरी की।

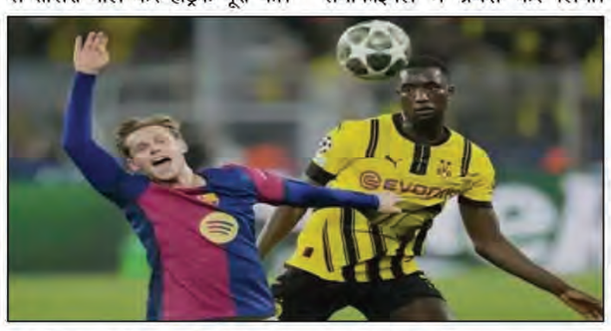

इसी के साथ वे इस सत्र में यूएफा चैंपियंस लीग के सर्वोच्च गोल स्कोरर बन गए, उनके नाम अब 13 गोल हो गए हैं। हालांकि, इस बीच रामी बेन्सेबाइनी का आत्मघाती गोल डॉर्टमंड के लिए भारी पड़ गया और उनकी वापसी की उम्मीदों को झटका लगा।

बार्सिलोना ने बचाई बढ़त, सेमीफाइनल में पहुंची

डॉर्टमंड ने अंत तक बराबरी की कोशिश की, लेकिन बार्सिलोना ने अपनी बढ़त को कायम रखा और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। अब बार्सिलोना का सामना इंटर मिलान या बायर्न म्यूनिख से होगा।

मैच का कुल स्कोर:

पहला चरण: बार्सिलोना 4-0 डॉर्टमंड

दूसरा चरण: डॉर्टमंड 3-1 बार्सिलोना

कुल स्कोर: बार्सिलोना 5-3 डॉर्टमंड

कप्तान अजिंक्य रहाणे ने लिया केकेआर की हार का जिम्मा, बोले- 'हमने बेहद खराब बल्लेबाजी की'

एजेंसी

चंडीगढ़। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (आईपीएल 2025) में मंगलवार रात कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ 16 रन की हार का सामना करना पड़ा।

मैच के बाद प्रेजेंटेशन में रहाणे ने कहा, जो भी हुआ वो आप सबने देखा। काफी निराश हूं। मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूं। बतौर कप्तान मैंने भी गलत शॉट खेला, भले ही गेंद मिस कर रही थी, लेकिन वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। हमने एक बैटिंग यूनिट के तौर पर बहुत खराब प्रदर्शन किया। हमारे बॉलर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, 111 रन पर पंजाब जैसी मजबूत टीम को रोकना आसान नहीं था। रहाणे ने माना कि 112 रन का टारगेट चेज़ करना आसान था, लेकिन बल्लेबाज़ों ने लापरवाही से शॉट खेले। उन्होंने यह भी बताया कि अपने विकेट के वक्त उन्होंने डीआरएस नहीं लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि दोनों बैटर्स के बीच कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मैं रिव्यू ले लूं और फिर बाद में वो एक बचा रहे। कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। शायद अंपायर का कॉल या गेंद लग भी सकती थी। लेकिन कोई शिकायत

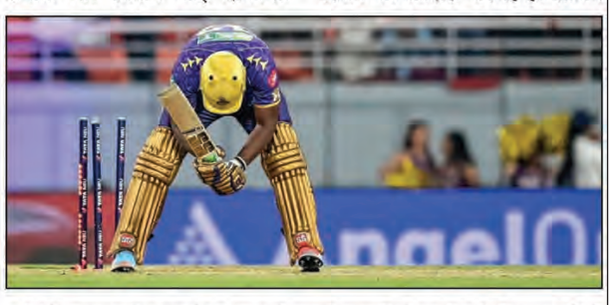

नहीं है। सच तो यह है कि हमने बैटिंग यूनिट के तौर पर बेहद खराब क्रिकेट खेला।

रहाणे और अंगकृष रघुवंशी (37 रन, 28 गेंद) ने तीसरे विकेट के लिए 55 रन जोड़कर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन रहाणे के आउट होते ही मैच का रुख पलट गया। युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लेकर केकेआर की मिडल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। आखिरी 7 विके**ट महज 23 रन पर गिर गए।** रहाणे ने कहा, आजकल बैटर्स मैदान पर अच्छे दिखने के लिए बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टी20 क्रिकेट सिर्फ सिक्स-चौकों का खेल नहीं है। हालात को पढ़ना और उसी हिसाब से खेलना ज़रूरी है। हमें उस वक्त सिंगल-डबल लेकर पारी को आगे ले जाना चाहिए था। विकेट फ्लैट नहीं था, बॉलर्स को मदद मिल रही थी। लेकिन हमने ज़रूरी धैर्य और गेम अवेयरनेस नहीं दिखाई।

ओलंपिक 2028: क्रिकेट के आयोजन स्थल की घोषणा, अमेरिका के पोमोना में बनेगा खास अस्थायी स्टेडियम

एजेंसी

नई दिल्ली। ओलंपिक खेलों में 124 साल बाद क्रिकेट की वापसी होने जा रही है और इसके लिए अमेरिका के साउदर्न कैलिफोर्निया के पोमोना शहर में खास अस्थायी स्टेडियम बनाया जाएगा। जो इस खेल का आयोजन स्थल होगा। एलए 28 ओलंपिक आयोजक समिति ने इसकी घोषणा की। यह आयोजन स्थल 'फेयरप्लेक्स' कहलाता है, जो 500 एकड़ में फैला हुआ है और 1922 से लॉस एंजेलिस काउंटी फेयर की मेजबानी कर रहा है।

14 जुलाई से 30 जुलाई तक होंगे ओलंपिक 2028

लॉस एंजेलिस में 14 जुलाई से 30 जुलाई 2028 तक होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट 1900 के

बाद पहली बार शामिल होगा। तब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच दो दिवसीय मुकाबला खेला गया था। अब क्रिकेट का आयोजन तेज़-तर्रार और रोमांचक टी20 फॉर्मेट में होगा, जिससे दुनियाभर के नए दर्शकों को जोड़ने की कोशिश होगी।

पुरुष और महिला वर्ग में 6-6 टीमें लेंगी हिस्सा

एलए 28 ओलंपिक में पुरुष और महिला वर्ग में कुल 6-6 टीमें खेलेंगी। इसके लिए क्रिकेट को 90 एथलीट कोटा मिला है, यानी हर टीम में 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड होगा। हालांकि क्वालिफाइंग रास्ता और कट-ऑफ्स का ऐलान अभी नहीं हुआ है।

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने दी प्रतिक्रिया

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा, हम क्रिकेट के लिए ओलंपिक में वेन्यू की घोषणा का स्वागत करते हैं। यह हमारे खेल की ओलंपिक में वापसी की तैयारी की दिशा में अहम कदम है। क्रिकेट वैसे तो एक बेहद लोकप्रिय खेल है, लेकिन ओलंपिक जैसे मंच पर टी 20 फॉर्मेट में खेलना नई ऑडियंस तक पहुंचने का शानदार अवसर होगा।

इन नए खेलों को भी मिली जगह: एलए 28 ओलंपिक में क्रिकेट के अलावा बेसबॉल/सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रॉस (सिक्सेस) और स्क्वैश को भी जगह मिली है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक में भी क्रिकेट को बरकरार रखा जाएगा। वहां गाबा स्टेडियम के आखिरी मैच के तौर पर क्रिकेट फाइनल कराने की योजना है, इसके बाद स्टेडियम को तोड़ने की तैयारी है।

पंजाब एफसी को मिला सर्वश्रेष्ठ एलीट यूथ प्रोग्राम का आईएसएल अवॉर्ड

एजेंसी

मोहाली। पंजाब एफसी को इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2024-25 सीजन के लिए सर्वश्रेष्ठ एलीट यूथ प्रोग्राम अवॉर्ड से नवाजा गया है।

यह सम्मान क्लब के युवा विकास में उत्कृष्ट योगदान और अकादमी से तैयार खिलाड़ियों को सीनियर टीम में सफलतापूर्वक शामिल करने के लिए दिया गया है। इस सीजन में पंजाब एफसी ने लीग की सबसे युवा टीम उतारी, जिसकी औसत उम्र 25 वर्ष और 216 दिन रही। यह क्लब की दीर्घकालिक सोच, स्थिरता और युवा प्रतिभाओं में विश्वास को दर्शाता है। सत्र के दौरान क्लब के नौ अकादमी स्नातकों ने सीनियर टीम में जगह बनाई, जिनमें से छह खिलाड़ियों ने इस मंच पर डेब्यू किया। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि क्लब ने अंडर-23 खिलाड़ियों को कुल 7,522 मिनट का खेल समय दिया, जो इस सीजन में किसी भी क्लब द्वारा सर्वाधिक है। हेड कोच पानागियोटिस डिल्मपेरिस का युवाओं में भरोसा क्लब की सफलता की नींव बना। प्रमवीर सिंह इस सीजन में आईएसएल इतिहास के सबसे युवा स्टार्टर बने, जबकि सिंगमायुम शामी सबसे युवा गोल स्कोरर के रूप में उभरे। विशाल यादव ने तीसरे सबसे युवा डेब्यू करने वाले खिलाड़ी का गौरव पाया, और मुहम्मद सुहैल तीसरे सबसे युवा असिस्ट देने वाले खिलाड़ी बने।

आईपीएल 2025: रोमांचक मुकाबले में पंजाब ने कोलकाता को 16 रन से हराया

एजेंसी

मुल्लांपुर (पंजाब)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के 31वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स को 16 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ पंजाब ने आईपीएल इतिहास में सबसे छोटे स्कोर (112 रन) को सफलतापूर्वक डिफेंड करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 111 रन बनाए। टीम की शुरुआत आक्रामक रही और पहले तीन ओवर में ही स्कोर 39 तक पहुंच गया। हालांकि इसके बाद विकेटों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि पूरी टीम 19.4 ओवर में 111 रन पर सिमट गई। पंजाब की ओर से प्रभसिमरन सिंह ने

30, प्रियांश आर्या ने 22 और शशांक सिंह ने 18 रन का योगदान दिया। केकेआर के लिए हर्षित राणा ने तीन विकेट चटकाए, जबकि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरायण ने दो-दो विकेट झटके। 112 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की शुरुआत अच्छी रही और पावरप्ले में टीम ने 50 रन जोड़ लिए। मगर कप्तान अजिंक्य रहाणे के आउट होते ही मैच ने करवट ली और केकेआर की पारी लड़खड़ा गई। देखते ही देखते टीम ने 7 रन के अंदर (72 से 79 के बीच) अपने पांच विकेट गंवा दिए और 15.1 ओवर में 95 रन पर ऑलआउट हो गई। कोलकाता की ओर से अंगकृष रघुवंशी ने सर्वाधिक 37 रन बनाए, जबकि रहाणे और आंद्रे रसेल ने 17-17 रन का योगदान दिया। पंजाब के लिए यजुवेंद्र चहल ने घातक गेंदबाजी करते हुए चार विकेट लिए, वहीं मार्को यानसेन ने तीन सफलताएं हासिल कीं। अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट और ग्लेन मैक्सवेल को भी एक-एक विकेट मिला।

भारतीय महिला हाकी टीम में पूजा का चयन

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय महिला हाकी टीम की सदस्य पूजा यादव का भारतीय महिला हाकी टीम में हो गया। सूर्यबली यादव पी.जी. कालेज, देवकली, सरायख्वाजा, जौनपुर की बीए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा पूजा यादव का चयन होने पर विश्वविद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गयी। पूजा यादव की इस सफलता से कुलपति प्रो. वन्दना सिंह, कुलसचिव महेन्द्र कुमार, परीक्षा नियन्त्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह, सचिव खेलकूद परिषद प्रो. ओमप्रकाश सिंह ने बधाई दिया है। विश्वविद्यालय की हॉकी महिला टीम लगातार अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही है। खेलो इण्डिया विश्वविद्यालयीय खेल के लिए अर्हता प्राप्त कर रही है।

चौथे बाबा दीप सिंह हॉकी और बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 17 अप्रैल से, खालसा कॉलेज करेगा मेजबानी

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में 17 अप्रैल से चौथे बाबा दीप सिंह हॉकी (पुरुष व महिला) और बास्केटबॉल (पुरुष व महिला) टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट हर वर्ष आयोजित किया जाता है और इस बार भी खेल प्रेमियों को शानदार मुक़ाबले देखने को मिलेंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन हॉकी ओलंपियन और 1975 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य अशोक दिवान के हाथों होगा। इस अवसर पर पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री गौतम वढेरा और मेज़बान खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर गुरमोहिंदर सिंह भी मौजूद रहेंगे। हॉकी में 10 टीमें, बास्केटबॉल में 16 टीमें लेंगी हिस्सा

कॉलेज की डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, इंदरप्रीत कौर नंदा के अनुसार टूर्नामेंट में पुरुष हॉकी वर्ग में 6 टीमें और महिला हॉकी वर्ग में 4 टीमें उतरेंगी। पुरुष वर्ग में मुकाबले लीग कम नॉकआउट फॉर्मेट में जबकि महिला वर्ग में राउंड रॉबिन लीग फॉर्मेट में खेले जाएंगे।

21 अप्रैल से शुरू होगी बास्केटबॉल प्रतियोगिता

बास्केटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत 21 अप्रैल से होगी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 8-8 टीमें भाग लेंगी। यह प्रतियोगिता भी लीग कम नॉकआउट फॉर्मेट में खेली जाएगी और फाइनल मुकाबले 25 अप्रैल को आयोजित किए जाएंगे। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का

आयोजन पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के सहयोग से किया जा रहा है। आयोजन समिति को उम्मीद है कि टूर्नामेंट के ज़रिए युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा।

अंतर मंडलीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए टीम चयनित

एजेंसी

मुरादाबाद। ज़िला फुटबॉल एसोसिएशन महासचिव मुहम्मद नासिर कमाल ने बताया कि कानपुर में आयोजित अंडर- 20 पुरुष अंतर मंडलीय प्रदेश स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता-2025 (मुहम्मद शमसुद्दीन बाबू भाई ट्रॉफी) का आयोजन 16 से 21 अप्रैल तक किया जाएगा। इसमें प्रदेश की समस्त 18 मण्डलों की टीमें प्रीतिभाग करेंगी। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु मुरादाबाद मण्डल की टीम का चयन आज एमपीएस के मैदान पर किया गया। चयनकर्ताओं सहायक सचिव

आमिर मिर्ज़ा, सुरेंदर पाल सिंह व यूपी पुलिस के सीनियर फुटबॉल खिलाड़ी नासिर हुसैन ने टीम का चयन किया। नासिर कमाल ने बताया कि चयनित टीम में जाने आलम, मुहम्मद अमन, मुहम्मद हसन, अभय कुमार, मुहम्मद राजा, गणेश, मुहम्मद एहसान, निखिल कुमार, सरताज मुमताज़, हर्षुल चाहल, अनस हुसैन, मुहम्मद शाहनूर, जुबैर खान, तनिष्क प्रतियाल, आमिर अब्बास, प्रियांशु जैन के अलावा टीम कोच नासिर हुसैन रहेंगे। टीम में आरक्षित खिलाड़ी देव राज, अरहम खान, मुहम्मद मोनिस, रयान खान रहेंगे।

आईडब्ल्यूएलएफ एथलीट आयोग की अध्यक्ष चुनी गईं मीराबाई चानू

एजेंसी

नई दिल्ली। ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एस. सतीश कुमार को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ (आईडब्ल्यूएलएफ) के एथलीट आयोग का क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया है। इन दोनों का कार्यकाल चार साल का होगा। मीराबाई भारत की सबसे सम्मानित भारोत्तोलकों में से एक हैं, जिनके

नाम कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड और ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं। कुल भारोत्तोलन में उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 205 किग्रा है, (स्नैच में 86 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 119 किग्रा) जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। उनका 88 किग्रा भार उठाकर स्नैच में भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। टोक्यो 2020 ओलंपिक में वह रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनीं, जिसने देश में इस खेल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। इससे पहले 2017 में उन्होंने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली दो दशकों से अधिक समय में पहली भारतीय बनकर 22 साल की प्रतीक्षा को समाप्त किया। सतीश ने गोल्ड कोस्ट में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था। पुरुषों के 77 किग्रा वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए, उन्होंने कुल 317 किग्रा - स्नैच में 144 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 173 किग्रा भार उठाया। यह उनका लगातार दूसरा राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक था। इससे पहले उन्होंने 2014 में ग्लासगो में यह खिताब जीता था।

आलिया भट्ट

और रणबीर कपूर की शादी को तीन साल हुए पूरे, कपल की प्यारी तस्वीर देख लोग क्या बोल गए

साल 2022 में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी के बंधन में बंधे थे, जिसके बाद से ही ये कपल लोगों का फेवरेट बन गया है. हालांकि, दोनों की शादी को 14 अप्रैल को तीन साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ये कल की ही बात लगती है. दोनों अपने रिश्ते के साथ ही साथ अपनी बेटी राहा को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं. हालांकि, दोनों की तीसरी एनिवर्सरी की बात की जाए, तो इस खास मौके पर आलिया ने काफी लविंग पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने लंबे वक्त तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 14 अप्रैल साल 2022 में शादी कर ली थी. दोनों ने काफी सिंपल तरीके से शादी रचाई थी. दोनों ने अपनी तीसरी सालगिरह के खास मौके पर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में आलिया और रणबीर की क्यूट फोटो है. इस पोस्ट के साथ आलिया ने कैप्शन शेयर करते हुए एक्टर को अपना घर बताया है.

लोगों ने भी दी दोनों को बधाई

बी-टाउन कपल की इस फोटो को उनके फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आलिया भट्ट की सास नीतू कपूर ने दिल वाली इमोजी भेजी है, तो वहीं उनकी मां सोनी राजदान ने भी कपल पर प्यार बरसाते हुए इस खास दिन की बधाई दी है. परिवार वालों के अलावा बॉलीवुड के और भी स्टार्स ने कपल को उनके एनिवर्सरी पर उन्हें बधाई दी है. इस फोटो में आलिया रणबीर के कंधे पर अपना सिर रखे नजर आ रही हैं.

साथ करने वाले हैं फिल्म

आलिया की बात की जाए, तो उन्होंने रणबीर को डेट करने से पहले कई बार उनके लिए अपने प्यार का इजहार किया है. हालांकि, फिलहाल दोनों ही स्टार अपने-अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में बिजी हैं.

दोनों की फिल्मों की बात की जाए, तो आलिया और रणबीर जल्द ही साथ में स्क्रीन शेयर करते नजर आने वाले हैं. दोनों संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में साथ दिखेंगे. इसके साथ ही साथ दोनों अपने खुद के अलग-अलग फिल्मों पर भी काम कर रहे हैं.

मां-बेटे के रिश्ते को गलत नजर... निशा रावल का फूटा गुस्सा, बेटे पर उंगली उठाने वालों को लगाई फटकार

टीवी एक्ट्रेस निशा रावल हाल ही में अपने बेटे कविश के साथ वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर सुर्खियों में थीं. वीडियो में कविश अपनी मां के सीने को छूते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हुई. अब इस मामले पर निशा रावल ने खुलकर अपनी राय रखी है और इस दौरान मां-बेटे के रिश्ते पर उंगली उठाकर उन्हें ट्रोल करने वालों को भी निशा की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है.दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो में निशा रावल मुंबई में हुए एक पार्टी के दौरान पैपराजी के लिए पोज दे रही थीं, तभी उनका सात साल का बेटा कविश अनजाने में उनके सीने को छूता हुआ और उनसे मस्ती करता हुआ नजर आया. इस मामूली घटना को कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने गलत नजर से देखा और निशा-कविश की आलोचना करना शुरू कर दिया. इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए निशा रावल ने कहा कि ऐसे लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए जो एक पवित्र मां-बेटे के रिश्ते को गलत नजर से देखते हैं.

ट्रोलर्स पर फूटा निशा रावल का गुस्सा

मुंबई में एक फैशन शो के रेड कार्पेट पर जब निशा रावल से इस वायरल वीडियो पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई, तो उन्होंने इंस्टेंट बॉलीवुड से बातचीत में कहा, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो एक मां-बेटे के रिश्ते को गलत नजर से देखते हैं. ये खोट उनके मन में है, इसलिए उस पर मैन कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी. अब उसके बारे में क्या ही बोल सकते हैं ? निशा की इस रिएक्शन के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स निशा के सपोर्ट में आगे आए हैं.

पति करण मेहरा से अलग हो गई हैं निशा

गौरतलब है कि इससे पहले साल 2021 में निशा रावल ने अपने पूर्व पति करण मेहरा पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, जिसके बाद करण मेहरा को गिरफ्तार भी किया गया था. निशा ने मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बहस के दौरान करण ने उन्हें दीवार पर धक्का दिया और उनके सिर पर चोट पहुंचाई थी. निशा ने ये भी दावा किया था कि करण का चंडीगढ़ में शूटिंग के दौरान दिल्ली की एक लड़की के साथ अफेयर था. निशा रावल और करण मेहरा ने 2012 में शादी की थी और 2017 में उनके बेटे कविश का जन्म हुआ था.

सलमान-सनी देओल को जब आमिर ने अकेले दी थी पटखनी, 29 साल पुरानी फिल्म ने कमा डाले थे 76 करोड़

सनी देओल और सलमान खान की फिल्में हाल ही में रिलीज हुई हैं. सलमान की 'सिकंदर' 30 मार्च को सिनेमाघरों में आई थी लेकिन इसे दर्शकों ने नकार दिया है. वहीं सनी देओल की फिल्म 'जाट' ने 10 अप्रैल को दस्तक दी थी जिसे फैंस से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. सलमान और सनी की फिल्मों का एक दूसरे से क्लैश हो रहा है लेकिन कभी दोनों एक्टर साथ में भी बड़े पर्दे पर नजर आ चुके हैं.

सिकंदर और जाट बड़े पर्दे पर आमने-सामने हैं. लेकिन आज से 29 साल पहले दोनों एक्टर्स ने साथ में काम किया था और उनकी फिल्म को दर्शको ने काफी पसंद किया था. लेकिन दोनों की जोड़ी पर अकेले आमिर खान भारी पड़ गए थे. आमिर की भी उसी साल एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा दिया था और सलमान-सनी की फिल्म को पछाड़ते हुए टिकट खिड़की पर 76 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था.

सलमान-सनी की 'जीत' ने कमाए थे 28 करोड़

सलमान खान और सनी देओल की जिस फिल्म के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं वो है 'जीत'. जीत साल 1996 में रिलीज हुई थी और ये उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी थी. जीत में सनी और सलमान खान के साथ करिश्मा कपूर ने भी लीड रोल निभाया था. राज कंवर के डायरेक्शन में बनी जीत का बजट 5.6 करोड़ रुपये था. वहीं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था और ये हिट साबित हुई.

आमिर की 'राजा हिन्दुस्तानी' ने छापे थे 76 करोड़

साल 1996 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म नाना पाटेकर और जैकी श्रॉफ की 'अग्नि साक्षी' थी जिसने 31 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए थे. जबकि पहले नंबर पर आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'राजा हिंदुस्तानी' काबिज रही. राजा हिन्दुस्तानी की कहानी के साथ ही इसके गानों ने भी फैंस के दिलों में खास जगह बनाई थी. आमिर और करिश्मा कपूर की लव स्टोरी को फैंस ने काफी पसंद किया था. इस फिल्म का बजट 6 करोड़ रुपये से भी कम था, लेकिन इसने वर्ल्डवाइड 76 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करके 1996 में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे.

ये है मोहब्बतें' फेम

दिव्यांका त्रिपाठी

को हुआ डेंगू, चिंतित हुए फैंस

'ये है मोहब्बतें' की इशिमा यानी टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी सेहत के बारे में अहम जानकारी शेयर की है. उन्होंने अपनी स्टोरी में थर्मामीटर की फोटो शेयर करते हुए बताया कि वो कुछ दिनों से बीमार थीं और जांच कराने पर उन्हें पता चला कि उन्हें डेंगू हुआ है.

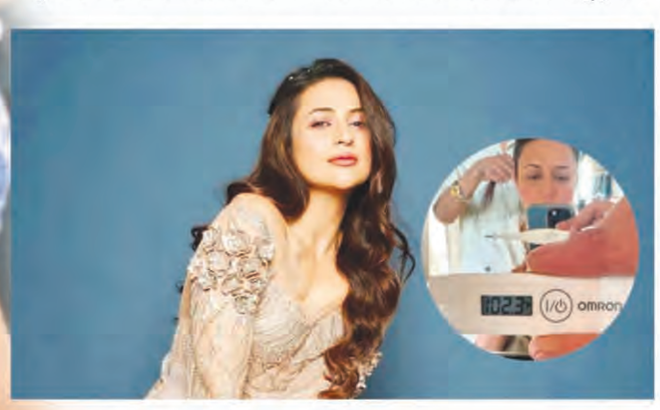

उम्मीद है कि वो बड़ी ही जल्दी ठीक हो जाएंगी और इस उम्मीद के साथ उन्होंने अपनी स्टोरी में चियर्स भी लिखा है. दिव्यांका की इस स्टोरी के बाद उनके फैंस ने उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करना शुरू कर दिया है.

दरअसल दिव्यांका त्रिपाठी को कुछ दिन पहले एक अवार्ड फंक्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था. 102 बुखार होने के बावजूद दिव्यांका इस अवार्ड फंक्शन में शामिल हुईं. हालांकि तब वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थीं कि उन्हें डेंगू हुआ है. लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका बुखार ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तब उन्होंने अपनी टेस्ट कराई. टेस्ट करने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें डेंगू हुआ है.

टीवी से कुछ समय के लिए दूर हैं दिव्यांका

'बनू मैं तेरी दुल्हन', ' ये हैं मोहब्बतें' जैसे टीवी सीरियल और 'खतरों के खिलाड़ी' जैसे एडवेंचर रियलिटी शो में अपना कमाल दिखाने के बाद दिव्यांका ने टीवी से दूरियां बनाई हैं.

कुछ दिन पहले वो जियो की वेब सीरीज 'मैजिक ऑफ शिरी' में जादूगर की भूमिका में नजर आई थीं. इस सीरियल में उनके साथ जावेद जाफरी और नामित दास अहम भूमिका में थे. दिव्यांका की पॉपुलैरिटी को देखकर उन्हें कई बार 'खतरों के खिलाड़ी' ऑफर किया गया. लेकिन उन्होंने हमेशा इस शो में शामिल होने से इनकार कर दिया. इस बारे में बात करते हुए उन्होंने टीवी9 हिंदी डिजिटल से कहा था कि उन्हें नहीं लगता फिलहाल उनके लिए इस शो में शामिल होने का सही वक्त है.

कांग्रेस ही संघ-भाजपा को हराएगी: राहुल गांधी

मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करेगी

एक सप्ताह में गुजरात की अपनी दूसरी यात्रा पर लोकसभा में विपक्ष के नेता ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जमकर निशाना साधा

मोदासा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को गुजरात में अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ता हतोत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन केवल उनकी पार्टी ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा को हरा सकती है। एक सप्ताह में गुजरात की अपनी दूसरी यात्रा पर लोकसभा में विपक्ष के नेता ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रतिबद्धता जताई कि कांग्रेस हार नहीं मानेगी। भाजपा को हराने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। जो कार्यकर्ता बूथ पर मजबूत है, हम उसका साथ देंगे। भाजपा के पश्चिमी राज्य पर लगभग 30 वर्षों के शासन को खत्म कर देंगे। उन्होंने गुजरात को (जहां कांग्रेस कभी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत थी) विपक्षी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य बताया। राहुल गुजरात में संगठन को नया रूप देने के लिए जिला इकाइयों को मजबूत करने की एक पायलट परियोजना शुरू करने के बाद अरवल्ली जिले के मोडासा शहर में बूथ स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। गुजरात में 2027 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राहुल ने कहा, 'गुजरात कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। हम गुजरात में हतोत्साहित दिखते हैं, लेकिन हम भाजपा को राज्य में हरा देंगे। मैं यहां आपको यह बताने के लिए हूं कि यह मुश्किल नहीं है। हम निश्चित रूप से यह कार्य पूरा करेंगे। केवल कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और भाजपा को हरा सकती है।'

केंद्र सरकार कांग्रेस को निशाना बना रही: मल्लिकार्जुन खरगे

नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज यहां भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विफलताओं को छिपाने के लिए कांग्रेस को निशाना बना रही है। यह आरोप प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में अभियोजन शिकायत के बाद लगाया गया है। खरगे ने एक एक्स पोस्ट में दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन नियंत्रण से बाहर हो रहा है। इस सरकार के पास कोई दृष्टि या समाधान नहीं है, वह महज अपनी गलतियों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए पांच महत्वपूर्ण तथ्य काफी हैं। उहोंने कहा कि व्यापार घाटा तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। टैरिफ और व्यापार युद्ध पर कोई स्पष्ट योजना नहीं है और समाधान की बजाय केवल खोखले शब्द और अनुत्पादक दौरे हुए हैं। उन्होंने आरबीआई के मार्च 2025 के एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि 90% उपभोक्ताओं ने बताया कि कमोडिटी की कीमतें बढ़ गई हैं। परिणामस्वरूप, 80% से अधिक ने कहा कि उनके खर्च में वृद्धि हुई है, भले ही आय में वृद्धि नहीं हुई। एफएमसीजी फर्मों की राजस्व वृद्धि वित्त वर्ष 25 में धीमी होकर केवल 5% रह गई, जबकि मार्जिन में कोई सुधार नहीं हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दिसंबर 2024 तक ईंधन पर करों और शुल्कों के रूप में 39 लाख करोड़ रुपये एकत्र करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि एलपीजी की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी करने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर बोझ बढ़ गया। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के हवाले से उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी के बारे में कहा कि स्नातकों की बेरोजगारी दर 13% और युवा बेरोजगारी दर 10.2% है। देश के 23 में से 22 आईआईटी और 25 में से 23 आईआईआईटी में प्लेसमेंट में गिरावट देखी गई और एनआईटी में प्लेसमेंट में 11% की गिरावट देखी गई। एफडीआई में गिरावट से भारत को होने वाले नुकसान की चर्चा करते हुए खरगे ने कहा कि अप्रैल से जनवरी 2024-25 तक भारत में शुद्ध एफडीआई 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम था जबकि अप्रैल से जनवरी 2012-13 तक यह 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस की इटली और भारत यात्रा की घोषणा

वॉशिंगटन

व्हाइट हाउस के उपराष्ट्रपति कार्यालय ने घोषणा की है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस अपने परिवार के साथ 18 से 24 अप्रैल तक इटली और भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के नेताओं के साथ आर्थिक सहयोग और भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा करना है। घोषणा के अनुसार, उपराष्ट्रपति वेंस अपनी यात्रा की शुरूआत इटली की राजधानी रोम से करेंगे, जहां वे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। साथ ही वे वेटिकन सिटी में कार्डिनल पिएत्रो पैरोलीन, जो वेटिकन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, से भी मिलेंगे। इन बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर संवाद होने की संभावना है। इसके बाद उपराष्ट्रपति वेंस भारत आएंगे, जहां वे नई दिल्ली, जयपुर और आगरा का दौरा करेंगे। भारत में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से निर्धारित है। दोनों नेता आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे, जिसमें व्यापार, निवेश, रणनीतिक साझेदारी और सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल होंगे।

इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति वेंस और उनका परिवार भारत के प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों का भी दौरा करेगा। यह यात्रा संस्कृति और द्विपक्षीय संबंधों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। व्हाइट हाउस की इस घोषणा से स्पष्ट है कि अमेरिका, इटली और भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह दौरा न केवल राजनयिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक सहयोग की दिशा में भी एक सार्थक प्रयास है।

मंडी में डीसी आफिस को बम से उड़ाने की धमकी भरी ई-मेल

मंडी

बुधवार सुबह पौने ग्यारह बजे के करीब उपायुक्त कार्यालय में लगे सायरन अचानक बजने लगे, तो लोगों को लगा कि भूकंप जैसी आपदा को लेकर प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा होगा। लेकिन उपायुक्त कार्यालय परिसर को बम से उड़ा देने की धमकी भरी मेल मिलने की बात जब लोगों को पता चली तो अफरातफरी मंच गई।

सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को चार फीसदी कोटा, विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा

बंगलूरू

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रख लिया है। राजभवन के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि राज्यपाल गहलोत ने विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित कर दिया और इसे कर्नाटक के विधि एवं संसदीय कार्य विभाग को भेज दिया। अब राज्य सरकार इस विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगी।

कर्नाटक विधानमंडल के दोनों सदनों से बिल पारित

बता दें कि, राज्य में भाजपा के विरोध के बावजूद कर्नाटक विधानमंडल के दोनों सदनों ने बिल पारित किया था। वहीं भाजपा ने इसे लेकर आरोप लगाया कि यह विधेयक अवैध है क्योंकि भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही आरोप लगाया कि इस विधेयक में सत्तारूढ़ कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति की बू आती है। पार्टी ने राज्य भर में चल रही अपनी जनआक्रोश यात्रा के दौरान इस विधेयक को प्रमुख मुद्दा बनाया है।

राज्यपाल ने क्या कहा?

राज्यपाल गहलोत ने कहा कि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता, क्योंकि यह समानता (अनुच्छेद 14), गैर-भेदभाव (अनुच्छेद 15) और समान अवसर (अनुच्छेद 16) जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

छत्तीसगढ़ : दो खूंखार इनामी नक्सली ढेर, एके-47 राइफल सहित अन्य हथियार एवं विस्फोटक बरामद

कोंडागांव

छत्तीसगढ़ में नारायणपुर और कोंडागांव जिले की सरहद पर बुरगुम के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने 2 खूंखार इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों की पहचान हलदर डिविजनल कमेटी मेंबर (डीव्हीसीएम) पर आठ लाख और रामे एरिया कमेटी मेंबर (एसीएम) पर पांच लाख का इनामी के रूप में हुई। शव के साथ मुठभेड़ स्थल से एक एके-47 राइफल एवं अन्य हथियार, विस्फोटक, एवं नक्सल सामग्री बरामद हुआ है ' कोंडागांव पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार ने बताया कि 15 अप्रैल को जिला कोंडागांव एवं नारायणपुर के सीमा से लगे किलम एवं बुरगुम के जंगल में डीआरजी एवं बस्तर फाइटर की संयुक्त पार्टी अभियान के लिए रवाना हुई थी। अभियान के दौरान 15 अप्रैल को लगभग देर शाम 8:30 बजे थाना पुंगारपाल क्षेत्रांतर्गत किलम-बुरगुम मरकामपाल के जंगल में सुरक्षाबलों एवं नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की सर्चिंग के दौरान दो नक्सलियों के शव के साथ एके-47 राइफल, अन्य हथियार, विस्फोटक एवं नक्सल सामग्री बरामद किया गया। मृत नक्सलियों की पहचान डिविजनल कमेटी मेंबर (डीव्हीसीएम) हलदर कश्यप एवं एरिया कमेटी मेंबर (एसीएम) रामे सोरी उर्फ रामू के रूप में हुई। मुठभेड़ में मारा गया डीव्हीसीएम हलदर पर 25 प्रकरण एवं एसीएमरामे पर तीन प्रकरण एवं दर्ज थे।

मुर्शिदाबाद हमले के कई पीड़ित परिवारों ने ली झारखंड में शरण

साहिबगंज

केंद्र सरकार की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित जाफराबाद गांव में एक समुदाय पर हुए हमले के बाद पीड़ित परिवारों ने झारखंड में शरण ली है। घटना में कई पीड़ित परिवार राज्य के साहिबगंज जिला के राजमहल स्थित बर्मन कॉलोनी पहुंचे और पनाह ली। घटना में 12 से अधिक एक समुदाय के लोगों की प्रतिष्ठानों में जमकर लूटपाट और महिलाओं से छेड़छाड़ की गई थी। यहां शरण लेने वाले एक समुदाय के लोगों में अब भी दशहत का माहौल है और आंखों में अपनों को खोने की पीड़ा है।

उन पीड़ित परिवार के कई लोगों ने बुधवार को बताया कि 12 अप्रैल उन लोगों के लिए तबाही का मंजर लेकर आया। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध तो एक बहाना था, लेकिन हकीकत में साजिश के तहत विशेष समुदाय की सामूहिक भीड़ ने हमारे परिवारों पर एकाएक हमला कर दिया। इस दौरान हमलोगों के घर पर बम भी फेंका गया, घरों और दुकानों में लूटपाट भी की गई । उनके सामने उनके परिजन के दो लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। वे लोग लगातार पुलिस को फोन से इसकी सूचना देते रहे लेकिन दो घंटे तक कोई भी पुलिस सहायता के लिए नहीं पहुंची। वे लोग किसी तरह से जान बचाकर अपने घरों में दुबके रहे। बाद में बहुत मुश्किल से एक एंबुलेंस के सहारे वे लोग अपनी जान बचाकर यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार पर से उन लोगों का भरोसा उठ गया है। इस सरकार में हमारे परिवारों की सुरक्षा हमेशा से संदेह के दायरे में रहा है। जब तक वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता तब तक पश्चिम बंगाल में उनका परिवार सुरक्षित नहीं है। पीड़ितों ने बताया कि उन लोगों की उम्मीद तब सिर्फ केंद्र सरकार पर टिकी हुई है।

भारत के जांबाजों को मिला सम्मान, मैकग्रेगर मेडल से नवाजे गए पांच सैनिक

नई दिल्ली

दिल्ली में आयोजित मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल समारोह के दौरान 2023 और 2024 के लिए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के पांच जवानों को उनके अद्वितीय साहस और सेवा के लिए मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल दिया गया। इस दौरान भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने देश के उन भूले-बिसरे जासूसों को सम्मान देने की अपील की, जिन्हें अंग्रेजों के समय तिब्बत, लद्दाख और अन्य सीमावर्ती इलाकों में गुप्त मिशनों पर रणनीतिक जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया था। जनरल चौहान ने कहा कि उन्हें भी अब मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किए जाने पर विचार करना चाहिए।

बता दें कि दिल्ली में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (यूएसआई) में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनरल चौहान ने कहा कि इन भारतीय जासूसों को पंडित कहा जाता था और वे "सर्वे ऑफ इंडिया" के लिए काम करते थे।

कुछ लोगों की सहूलियत को राजमार्ग प्रोजेक्ट में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि गांव के कुछ निवासियों की सहूलियत के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट में हस्तक्षेप करना बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राजमार्ग प्रोजेक्ट की प्रकृति लोक महत्व की है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट लोगों की सहूलियतों को देखते हुए तैयार की जाती है। राजमार्ग पर अंडर पास बनाकर हर गांव का सम्पर्क कायम रखना संभव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता बशर्ते ऐसा कार्य दुर्भाग्यपूर्ण व मनमानापूर्ण न किया गया हो। कोर्ट ने कहा कि राजमार्ग प्रोजेक्ट में बदलाव के लिए हस्तक्षेप का व्यापक असर होगा।

पहल सामाजिक संगठन व द इंडियन हाइट्स स्कूल और सेंटर फॉर साइट द्वारा ड्राइवरों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का किया आयोजन

दिव्या दिल्ली : बेहतर दृष्टि के लिए एक सामुदायिक प्रयास समाज सेवा के लिए समर्पित एक प्रतिष्ठित संगठन पहल ने द इंडियन हाइट्स स्कूल और सेंटर फॉर साइट के सहयोग से ड्राइवरों के लिए एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। यह सराहनीय आयोजन द इंडियन हाइट्स स्कूल परिसर में संपन्न हुआ। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य उन ड्राइवरों की नेत्र स्वास्थ्य जांच करना था, जो अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण अक्सर स्वास्थ्य जांच से वंचित रह जाते हैं। यह समझते हुए कि सुरक्षित ड्राइविंग में दृष्टि की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, आयोजकों ने इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया। इस शिविर में अनुभवी नेत्र चिकित्सकों और ऑप्टोमेट्रिस्ट की टीम ने व्यापक नेत्र परीक्षण किए। सेवाओं में विजुअल एक्यूटी टेस्ट, आंखों के दबाव की जांच, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और अपवर्तक दोष जैसी सामान्य नेत्र समस्याओं की स्क्रीनिंग शामिल थी। इसके अतिरिक्त, उपस्थित चिकित्सकों ने निःशुल्क परामर्श और आंखों की देखभाल से संबंधित उपयोगी सुझाव भी दिए। यह शिविर ड्राइविंग समुदाय में काफी लोकप्रिय रहा और बड़ी संख्या में ड्राइवरों ने इसमें भाग लिया। इस पहल ने नियमित नेत्र जांच के महत्व को उजागर किया और यह भी दशार्या कि हमारी सामुदायिक सोच, सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर कितनी गंभीर है। प्रतिभागियों ने पहल और द इंडियन हाइट्स स्कूल को इस उपयोगी आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अभियान की हर पहलू की जिम्मेदारी द इंडियन हाइट्स स्कूल के छात्रों ने स्वयं संभाली फंडरेजिंग, योजना निर्माण, लॉजिस्टिक्स और आउटरीच। यह प्रयास उनके नेतृत्व कौशल और सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस शिविर की सफलता और सकारात्मक प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर, पहल संस्था व द इंडियन हाइट्स स्कूल और सेंटर फॉर साइट निकट भविष्य में अन्य स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन की योजना बना रहे हैं। यह नेत्र जांच शिविर ऐसे कई स्वास्थ्य अभियानों की शुरूआत है, जिनका उद्देश्य समाज को स्वस्थ और सुरक्षित बनाना है। यह सराहनीय पहल न सिर्फ ड्राइवरों के स्वास्थ्य की चिंता का उदाहरण है, बल्कि यह भी दशार्ती है कि सामुदायिक सहयोग से बड़े बदलाव संभव हैं। इस आयोजन ने भविष्य के लिए एक मिसाल कायम की है और नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया है।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397